

संस्करण : मुंबई

वर्ष : 10

अंक : 317

पृष्ठ : 8

मूल्य : 2.00

शनिवार, 22 नवम्बर, 2025

जुनून है सच लिखने का

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित



3 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 'हेल्थ फॉर ऑल'....

4 शोर-शराबे का दौर, खोती हुई आवाजें, ...

7 दूसरे टेस्ट से गिल की गैरमौजूदगी पर...

संक्षिप्त न्यूज

दिवाला संहिता संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में, बैजयंत पांडा ने की प्रगति की पुष्टि

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा ने शुक्रवार को बताया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पर गठित प्रवर समिति शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आईबीसी संशोधन विधेयक पर गठित प्रवर समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा ने कहा कि रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में पेश की जाएगी और इस पर अच्छी प्रगति हुई है। पांडा ने एएनआई को बताया, 'बहुत अच्छी प्रगति हुई है और सदस्यों की भागीदारी भी अच्छी रही है।'

संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले, दिन में, प्रवर समिति ने अपनी बैठक की और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के प्रतिनिधियों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य प्राप्त किए, प्रत्येक खंड की जाँच की और एक सामान्य चर्चा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इससे पहले 21 अक्टूबर को, प्रवर समिति ने विधेयक पर विशेषज्ञों, उद्योग संघों, संगठनों और हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए थे। ये सुझाव 4 नवंबर तक स्वीकार किए जा रहे थे।

IBC (संशोधन) विधेयक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक बदलावों का प्रस्ताव करता है, और इसे व्यापक परीक्षण के लिए प्रवर समिति को भेजा गया था। विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआईआरपी) सहित नई अवधारणाओं को शामिल करना है, जिससे समाधान और परिसमापन दोनों चरणों में दक्षता बढ़ाने के प्रावधान और उपाय संभव होंगे।

भाषा युद्ध या विकास का मुद्दा? अन्नामलाई ने स्टालिन के आरोपों पर उठाए सवाल

चेन्नई। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने शुक्रवार को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा संस्कृत को मृत भाषा कहने की आलोचना करते हुए कहा कि द्रमुक सरकार भाषा पर बहस छेड़कर विकास और सुशासन जैसे वास्तविक मुद्दों से बच रही है। अन्नामलाई ने कहा कि संस्कृत को ज्यादा धन सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि भारत में तमिल विश्वविद्यालयों की तुलना में संस्कृत विश्वविद्यालय ज्यादा हैं, इसलिए नहीं कि सरकार इसे विशेष वरीयता देती है। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए, के अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को यह समझने की जरूरत है कि हमारे देश में कोई भी किसी भी भाषा को अतिरिक्त धन नहीं देता... यूपीए शासन के दौरान हमारे देश में संस्कृत विश्वविद्यालयों और तमिल विश्वविद्यालयों की संख्या पर नजर डालें। हमारे देश में संस्कृत विश्वविद्यालयों की संख्या तमिल विश्वविद्यालयों से ज्यादा है।

महागठबंधन की हार पर बिहार कांग्रेस में फूट: कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व पर जताया गुस्सा

पटना। बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पटना में विरोध प्रदर्शन किया और राज्य चुनावों में महागठबंधन के खराब प्रदर्शन के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रमुख राजेश राम और पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लवरु के खिलाफ रोष व्यक्त किया। एनडीए ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, 243 में से 202 सीटें जीतीं, जबकि महागठबंधन केवल 35 सीटें ही हासिल कर सका। सत्तारूढ़ गठबंधन ने 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया, जो दूसरी बार है जब एनडीए ने राज्य चुनावों में 200 सीटों का आंकड़ा पार किया। 2010 में, इसने 206 सीटें जीती थीं। इस बीच, एक दिन पहले, जनता दल (युनाइटेड) प्रमुख नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री

के रूप में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। नीतीश कुमार के अलावा कुल 25 नेताओं ने राजग के नेतृत्व वाले नए बिहार मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप



प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। नीतीश कुमार के अलावा कुल 25 नेताओं ने राजग के नेतृत्व वाले नए बिहार मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप

में शपथ ली। इनमें सम्राट चौधरी (भाजपा), विजय कुमार सिन्हा (भाजपा), विजय कुमार चौधरी (जद-यू), विजेन्द्र प्रसाद यादव (जद-यू), श्रवण कुमार (जद-यू), मंगल पांडे (भाजपा), दिलीप कुमार जायसवाल (भाजपा) और अशोक चौधरी (जद-यू) शामिल थे। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले अन्य लोगों में लेसी सिंह (जेडी-यू), मदन सहनी (जेडी-यू), नितिन नबीन (बीजेपी), राम कृपाल यादव (बीजेपी), एचएम (एस) के संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार (जेडी-यू), मोहम्मद जमा खान (जेडी-यू) और संजय सिंह टाडगर (बीजेपी) शामिल हैं। इस सूची में अरुण शंकर प्रसाद (बीजेपी), सुरेंद्र मेहता (बीजेपी), नारायण प्रसाद (बीजेपी), रमा निषाद (बीजेपी), लखेंद्र कुमार रीशन (बीजेपी) और श्रेयशी सिंह (बीजेपी) भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि यदि स्पटीकरण असंतोषजनक पाया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सुविचों के विशेष डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत एकत्रित गणना प्रपत्रों के अनुचित एवं अपूर्ण डिजिटलीकरण से संबंधित है। उन्होंने कहा, "बीएलओ को शुक्रवार दोपहर तक यह बताने का निर्देश दिया गया है कि वे सौंप गए कार्यों को ठीक से पूरा करने में क्यों विफल रहे।"



गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण का संचालन कर रहा है, जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं।

यह प्रक्रिया चार नवंबर को शुरू हुई और चार दिसंबर तक जारी रहेगी। मतदाता सूची का मसौदा नौ दिसंबर को जारी किया जाएगा।

निर्वाचन आयोग ने कोलकाता के सात बीएलओ को कारण बताओ नोटिस भेजा

कोलकाता। निर्वाचन आयोग ने कोलकाता के बेलियाघाटा निर्वाचन क्षेत्र के सात बृथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) गणना फॉर्म के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत एकत्रित गणना प्रपत्रों के अनुचित एवं अपूर्ण डिजिटलीकरण से संबंधित है। उन्होंने कहा, "बीएलओ को शुक्रवार दोपहर तक यह बताने का निर्देश दिया गया है कि वे सौंप गए कार्यों को ठीक से पूरा करने में क्यों विफल रहे।"



गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण का संचालन कर रहा है, जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं।

यह प्रक्रिया चार नवंबर को शुरू हुई और चार दिसंबर तक जारी रहेगी। मतदाता सूची का मसौदा नौ दिसंबर को जारी किया जाएगा।

केंद्र की नीतियों से मक्का किसान परेशान: सिद्धारमैया का आरोप, एमएसपी पर खरीद नहीं

बैंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार स्थापित नियमों के अनुसार मक्का नहीं खरीद रही है, जिससे किसान संकट में हैं। मुख्यमंत्री ने को एक बयान में कहा कि मैंने मक्के पर एक बैठक की है। मक्के के लिए खरीद केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

किसानों ने खरीद केंद्र खोलने की मांग की है। इसलिए, हमने किसानों के साथ बैठक की है। केंद्र ने 70 लाख मीट्रिक टन मक्का आयात किया है। इससे किसान प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार नियमों के अनुसार मक्का नहीं खरीद रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य

सरकार ने अधिकारियों और मंत्रियों को किसानों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। एक खरीद केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। मैं केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर उनसे कहीं और से आयात न करने का अनुरोध भी करूंगा। सरकार मक्के की समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई करेगी। उत्तरी कर्नाटक

के मक्का किसान मक्का खरीद केंद्र खोलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक को मक्का से इथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित कोटा बेहद कम है, जिसके कारण डिस्टिलरी द्वारा खरीद कम हो रही है।

डिजिटल अरेस्ट

धोखे से पैसा
ऐंठने का एक तरीका है!

ऐसे कॉल्स से सावधान रहें!

❌ परेशान न हों - डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती

❌ साझा न करें - निजी/वित्तीय जानकारी किसी को न बताएं

❌ भुगतान न करें

✅ cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें या सहायता के लिए 1930 पर कॉल करें



अधिक जानकारी के लिए,
<https://rbikehtahai.rbi.org.in/da> पर विजिट करें
फीडबैक देने के लिए,
rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें



जनहित में जारी
भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

बेटे ने माँ को अस्पताल में छोड़ा, हाईकोर्ट ने पुलिस की ढिलाई पर जताई नाराजगी, कहा- अंतरात्मा झकझोर देने वाला मामला

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 76 वर्षीय महिला को मुंबई के एक अस्पताल में उसके बेटे द्वारा कथित तौर पर छोड़ दिए जाने के बाद, मुंबई पुलिस और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण न्यायाधिकरण की निष्क्रियता सहानुभूति की कमी और गलत दिशा में कार्रवाई के लिए कड़ी आलोचना की। न्यायमूर्ति एस गडकरी और न्यायमूर्ति आरआर भोंसले की पीठ बांद्रा स्थित होली फैमिली अस्पताल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहाँ कुपोषित महिला को उसके बेटे ने भर्ती कराया था। हालाँकि उसने शुरुआत में लगभग 4.5 लाख रुपये का भुगतान किया था, लेकिन जब बकाया राशि 16 लाख रुपये हो गई, तो उसने कथित तौर पर बिल चुकाना बंद कर दिया, इलाज की लेकर कर्मचारियों से झगड़ा किया और अंततः गायब हो गया, जिससे उसकी माँ को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अस्पताल ने अदालत को सूचित

किया कि महिला को तीन बार अस्पताल में संक्रमण हुआ, जिससे छुट्टी के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट होने के बावजूद उसकी हालत बिगड़ गई।



अस्पताल की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि मामला पैसा का नहीं, बल्कि बेटे द्वारा अपनी माँ को घर ले जाने से इनकार करने का था, जिसकी वजह से उन्हें बेवजह अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल ने सुरक्षित छुट्टी दिला

में मदद के लिए मुंबई पुलिस और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल से कई बार संपर्क किया था। अदालत में वकील गौरी जोगलेकर के माध्यम से बेटे ने

दिया, यह देखते हुए कि डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से घर पर ही चिकित्सा देखभाल की सिफारिश की थी। पीठ ने टिप्पणी की, यह मामला न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है', तथा एक कमजोर बुजुर्ग मां की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद स्थिति को रेखांकित किया, जिसे अकेला छोड़ दिया गया है, जिसे उसवेक बेटे ने भावनात्मक समर्थन से वंचित कर दिया है, और वह कानूनी पचड़े में फंस गई है। सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से महाधिपक्ता डॉ. बोरेंद्र सराफ ने दलील दी कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत परित्याग की कार्रवाई की जाएगी। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अगर राज्य महिला की देखभाल का ज़िम्मा लेता है, तो वह बेटे को उसकी बांद्रा स्थित फ्लैट सहित उसकी किसी भी चल या अचल संपत्ति को संभालने से रोक सकता है।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं पालीताना के बीच चलाएगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस और पालीताना स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापित के अनुसार स्पेशल ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:- ट्रेन संख्या 09009/09010 बांद्रा टर्मिनस-पालीताना सुपरफास्ट स्पेशल (02 फेरें) ट्रेन संख्या 09009 बांद्रा टर्मिनस-पालीताना सुपरफास्ट स्पेशल रविवार, 23 नवंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 19:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 09:25 बजे पालीताना पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09010 पालीताना-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल सोमवार, 24 नवंबर, 2025 को

पालीताना से 20:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10:45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, गेटाद, धोला, सोनगढ़ और सिहोर (गुजरात) स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास



और जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे। ट्रेन संख्या 09009 एवं 09010 की बुकिंग 22 नवंबर 2025 से सभी पीआरएस काउंटर्स और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर लिंक पर यात्री वृत्तपत्र www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय एवं संवाद को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत 21 नवम्बर 2025 को अहमदाबाद एवं वडोदरा मंडलों के क्षेत्राधिकार में आने वाले माननीय सांसदों के साथ महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता की एक बैठक का आयोजन अहमदाबाद स्थित सर्किट हाउस में किया गया। बैठक में माननीय सांसदों ने वडोदरा मंडल द्वारा किये गये विकास कार्यों एवं प्रदान की गयी यात्री सुविधाओं पर संतोष जाहिर किया एवं जनप्रतिनिधि के रूप में महाप्रबंधक एवं मंडल रेल प्रबंधक से अपने क्षेत्र के रेल संबंधी सुझावों साझा किये। इस बैठक में माननीय सांसदों में श्री हसमुखभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व), श्री दिनेशभाई मकवाना (अहमदाबाद पश्चिम), श्रीमती शोभनाबेन बारैया (साबरकांठा) श्री मनसुखभाई वसावा (भरुच), श्री जशुभाई राठवा (छोटा

उदयपुर), श्रीमती अनिता चौहान (रतलाम) तथा श्री मयंकभाई नायक (राज्यसभा) उपस्थित रहे। भरुच से माननीय सांसद श्री मनसुखभाई वसावा



ने भरुच में अवतिका एक्सप्रेस, सूर्यनगरी एक्सप्रेस एवं लोकशक्ति एक्सप्रेस के स्टॉपेज को पुनर्बहाल करने और वंदे भारत एक्सप्रेस के भरुच में स्टॉपेज की मांग की। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए अंकलेश्वर और राजपिपला के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की, जो ब्रॉड गेज में परिवर्तित हो चुका है। छोटा उदयपुर से माननीय सांसद श्री जशुभाई राठवा ने नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदल चुके दभोई - मियागाम

कर्जन खंड पर ट्रेन सेवा की मांग रखी। रतलाम से माननीया सांसद श्रीमती अनिता चौहान ने प्रतानगर पर से छोटा उदपुर ट्रेन को जोबट तक विस्तारित

वर्ष 2025-26 के भारतीय रेल बजट में गुजरात राज्य के लिए ₹17,155 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह निवेश गुजरात में कनेक्टिविटी, औद्योगिक प्रगति और यात्री सुविधाओं को नई गति और दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि गुजरात में रेल विकास की गति लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में आणंद-गोधरा दोहरीकरण परियोजना रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक पूरी की गई है। इसी के साथ, भारतीय रेल पर विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर पश्चिम रेलवे के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण भी पूर्ण हो गया है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वडोदरा - रतलाम तृतीय एवं चतुर्थ लाइन परियोजना पश्चिम रेलवे की एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमता-वृद्धि परियोजना है। 259 किमी की इस परियोजना के लिए ₹8,884.74 करोड़ की स्वीकृति मिली है, जो पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता द्वारा बनाए की दिशा में एक बड़ा कदम है। वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने बैठक में माननीय सांसदों को वडोदरा मंडल की प्रगति पर विभिन्न नवीन यात्री सुविधाओं तथा विकासात्मक

उपलब्धियों से अवगत कराया। श्री भडके ने माननीय सांसदों को मंडल द्वारा दिवाली एवं छठ पूजा के दौरान किए गए उत्कृष्ट काउंड मैनेजमेंट प्रयासों, नॉन फेयर रिवेन्यू के? तहत वडोदरा मंडल द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही यात्री सुविधाएं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी के तहत प्रोजेक्ट सारथी, दिव्यांगों के स्टेशन पर क्रूचेज़, भरुच स्टेशन पर हेरिटेज लॉबी का विकास जैसे प्रयासों, यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गयी नई ट्रेन सेवाओं एवं ट्रेनों के अतिरिक्त स्टॉपेज करमण्ड के साथ साथ पुनर्विकसित किये जा रहे 10 अन्य स्टेशनों की प्रगति साझा की। रेलवे प्रशासन की ओर से महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री विवेक कुमार गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक वडोदरा श्री राजू भडके, पश्चिम रेलवे मुख्यालय से आए प्रमुख मुख्य रेल अधिकारी, RLDA तथा दोनों मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

बदलापुर रोड ओवर ब्रिज पर 18 नॉन स्टैंडर्ड स्टील गर्डरों के लॉन्चिंग हेतु विशेष ट्रैफिक व पावर ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल, मुंबई मंडल बदलापुर रोड ओवर ब्रिज पर फुट ओवर ब्रिज के लिए 37.2 मीटर स्पैन वाले 18 नॉन स्टैंडर्ड स्टील गर्डरों के लॉन्चिंग हेतु 350 एमटी रोड क्रेन का उपयोग करते हुए दिनांक 22/23.11.2025 से 03/04.12.2025 तक विशेष ट्रैफिक व पावर ब्लॉक परिचालित करेगा। ब्लॉक की तिथि: दिनांक 22/ 23.11.2025 (शनिवार/रविवार रात्रि) से 03/04.12.2025 (बुधवार/गुरुवार रात्रि) ब्लॉक अवधि: 02.00 बजे से 03.30 बजे तक (1 घंटे 30 मिनट) ट्रैफिक ब्लॉक सेक्शन: अप लाइन: वानगनी (क्रॉसओवर सहित)



सहित) ब्लॉक के कारण निम्न परिवर्तन किए जाएंगे: अप मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का डायवर्जन निम्नलिखित गाड़ियाँ कर्जत-पनवेल-दीवा मार्ग से डायवर्ट की जाएंगी, तथा

कल्याण स्टेशन से चढ़ने /उतरने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु पनवेल और ठाणे स्टेशनों पर ठहराव दिया जाएगा: ट्रेन नंबर 11020 भुवनेश्वर -

नेरुल स्टेशन पर 03:10 बजे से 03:30 बजे तक रेगुलेट किया जाएगा। ट्रेन नंबर 11140 होस्पेट - सीएसएमटी एक्सप्रेस को भिवपुरी रोड स्टेशन पर 03:17 बजे से 03:27 बजे तक रेगुलेट किया जाएगा। ब्लॉक अवधि में उपनगरीय ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन व ओरिजिनेशन एस1 सीएसएमटी-कर्जत लोकल (00:12 बजे प्रस्थान) अंबरनाथ स्टेशन पर शॉर्ट-टर्मिनेट की जाएगी। एस2 कर्जत-सीएसएमटी लोकल (02:30 बजे प्रस्थान) अंबरनाथ स्टेशन से 03:10 बजे शॉर्ट-ओरिजिनेट होकर चलेगी। इन ब्लॉकों का उद्देश्य रेलवे अवसंरचना का रख-रखाव और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यात्रियों से अनुरोध है कि होने वाली असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन को सहयोग करें।

नांदगाव - पिंपरखेड तीसरी रेलवे लाइन के निरीक्षण हेतु स्थानीय नागरिकों के लिये महत्वपूर्ण सूचना

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नांदगाव - पिंपरखेड तीसरी रेलवे लाइन के संरचनात्मक निरीक्षण के लिए मुख्य संरक्षा आयुक्त (कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी), सेंट्रल सर्कल का निरीक्षण 24 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इस निरीक्षण के तहत इंजन सीड परीक्षण निर्धारित किया गया है। निरीक्षण के दौरान उच्च गति से इंजन परीक्षण किया जाएगा, इसलिए रेलवे प्रशासन सभी नागरिकों, स्थानीय निवासियों, पशुपालकों एवं ग्रामीणों से अनुरोध करता है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें की वह रेलवे ट्रैक के

नजदीक न जाएं। रेलवे लाइन पर न करें, क्योंकि यह अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। पशुपालक अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक के आसपास न चराएं। रेलवे मार्ग पर कोई भी बाधा (वस्त्र, वाहन, मलबा आदि) उत्पन्न न करें। रेलवे प्रशासन इस मार्ग से जुड़े सभी गांवों के नागरिकों से सहयोग की अपील करता है ताकि यह संरक्षा जांच सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

पश्चिम रेलवे

मरम्मत कार्य

सीनियर DME (कंपनी) BCT, मुंबई सेंट्रल, ई-टेंडर नोटिस नंबर: M137-BL-ACWP, तारीख 20.11.2025 आमंत्रित करता है। काम का नाम: 05 साल के लिए ACWP वलसाड की वन टाइम रिपेयर और कॉम्प्रिहेंसिव AMOC। काम की लगभग लागत: 1,14,15,497.63 (सब मिलाकर)। बिड सिक्वोरिटी: 2,07,100/- सबमिट करने की तारीख और समय: 19.12.2025, 15:00 बजे तक। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। मैन्युअल ऑफर पर विचार नहीं किया जाएगा।

0826

हमें फॉलो करें [facebook.com/WesternRly](https://www.facebook.com/WesternRly)

पश्चिम रेलवे

विभिन्न कार्य

सीनियर डीएसटीई / एन / एमएसटी, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400008, निविदा सूचना संख्या: SG_216_2_140_WA, दिनांक: 17.11.2025 आमंत्रित करता है। कार्य और स्थान: सूरत की तरफ लूप लाइन नंबर 1 के 300 मीटर विस्तार के संबंध में प्लेटफार्म के विस्तार के साथ पूर्ण गुड्स लूप के रूप में उपयोग के लिए आउटडोर सिग्नलिंग वस्तुओं की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, उकाई सोनगढ़ स्टेशन पर एएसडीएसी का प्रावधान। कार्य की अनुमानित लागत: 1,48,39,208.22। ईएमडी: 2,24,200/-। जमा करने की तिथि और समय: 31.12.2025, 15:00 बजे तक। खुलने की तिथि और समय: ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं।

0811

हमें फॉलो करें [facebook.com/WesternRly](https://www.facebook.com/WesternRly)

नेरुल में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण खुशी-खुशी पूरा हुआ

नेरुल हॉस्पिटल में हेल्थकेयर को बेहतर बनाने वाली स्टेट-ऑफ-द-आर्ट माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी का उद्घाटन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा सेक्टर 1 नेरुल में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर लगाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण और सेक्टर 15 नेरुल में मासाहेब मीनाताई ठाकरे हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट स्कूल का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के वन मंत्री श्री गणेश नाइक, बेलापुर विधानसभा सदस्य श्री मंदाताई म्हात्रे, म्युनिसिपल कमिश्नर डॉ. कैलाश शिंदे की देखरेख में हुआ। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर श्री सुनील पवार, पूर्व श्दर्ड. संजीव नाइक, सिटी इंजीनियर श्री शिरीष आईवाड, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉ. प्रशांत जावेद, पूर्व मेयर श्री जयवंत सुतार और दूसरे गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति की औपचारिक तरीके से पूजा की गई।

इसके लिए रायगढ़ में पूजा करने वाले पुजारी श्री. कृष्ण पाटिल, श्री. ज्ञानेश्वर लोहार, श्री. अनंत केरेमानी मौजूद थे।

शिव का नाम जप रहे थे। नेरुल सेक्टर 1 में राजीव गांधी फ्लाईओवर के पास छत्रपति शिवाजी

इस चौक में गुंबद के आकार की छतरी के नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज की कांसे की मूर्ति लगाई गई है। 12 फीट ऊंची और 2.5 टन वजनी इस प्रेरणा देने वाली मूर्ति के आसपास के इलाके को ऐतिहासिक माहौल बनाने के लिए सुंदर बनाया गया है। वहां भाले पकड़े 4 मावलों और तोप लिए 3 मावलों की मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मूर्ति शिल्पकृति कला प्रतिष्ठान के मुख्य मूर्तिकार प्रो. मोरेश्वर पवार ने बनाई है। मूर्ति लगाने के लिए ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दूसरी सरकारी अथॉरिटी से परमिशन ले ली गई है। महाराष्ट्र के पूज्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र से प्रेरणा लेकर, सेक्टर 1 नेरुल के चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज की सिंहासनारूढ़ मूर्ति प्रेरणा देगी और एक नई भावना पैदा करेगी और इतिहास के प्रति गर्व जगाएगी।



पूरा चौक शिव भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। लोग 'छत्रपति शिवाजी महाराज की जय', 'जय भवानी - जय शिवाजी' जैसे नारे लगाते हुए भगवान

महाराज चौक बहुत मशहूर है और लोगो और लोगो की लगातार मांग थी कि इस जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई जाए। इसलिए,

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस ➡ पालिताना के बीच सुपरफास्ट विशेष ट्रेन चलाएगा				
ट्रेन नं०	प्रारम्भिक स्टेशन और स्थान	सेवा की तारीख	प्रस्थान	आगमन
09009	बांद्रा टर्मिनस -पालिताना	23.11.2025	19:25 hrs	09:25 hrs
09010	पालिताना - बांद्रा टर्मिनस	24.11.2025	20:30 hrs	10:45 hrs
हॉल्ट: बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, बोटाद, धोला, सोनगढ़ और सिहोर (गुजरात) स्टेशन दोनों दिशाओं में।				
कम्पोज़िशन: AC 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच।				
टाइमिंग, हॉल्ट और क्पोजिशन के बारे में डिटेल्ड जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।				
ट्रेन नंबर 09009 09010 की बुकिंग 22.11.2025 से सभी PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। उपर बताई गई ट्रेन स्पेशल ट्रेन के तौर पर स्पेशल किराए पर चलेगी।				
कृपया सभी रिज़र्व टिकटों के लिए ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ रखें				



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ‘हेल्थ फॉर ऑल’ कॉन्सेप्ट पर तुरंत रिस्पॉन्स

‘प्रोजेक्ट सुविता’ के तहत राज्य में 50 लाख से ज़्यादा परेंट्स का रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने डिजिटल मीडियम से मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज़ में बड़ी तरक्की की है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल और कॉन्सेप्ट पर शुरू किए गए ‘प्रोजेक्ट सुविता’ के तहत 50 लाख से ज़्यादा बच्चों के परेंट्स का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। इसके अलावा, इस पहल में 40 लाख प्रेनेट महिलाओं को रजिस्टर किया गया है। इस तरह, यह पहल राज्य में कुल 94 लाख बेनिफिशियरी तक पहुंच गई है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े स्टेट-कंट्रोल्ड और बिहेवियरल हेल्थ कम्युनिकेशन प्रोग्राम में से एक बन गया है।

जुलाई 2021 से, राज्य सरकार ने नॉन-प्राॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन ‘डेवलपमेंट कंसोर्टियम प्रोजेक्ट सुविता’ के साथ मिलकर एक SMS रिमाइंडर प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत,

बच्चों का समय पर वैक्सीनेशन और प्रेग्नेंट महिलाओं की मेटरनल हेल्थ केयर बढ़ाने के लिए पर्सनलाइज़्ड और समय



पर एएच मैसैज भेजे जाते हैं। हर मैसैज में वैक्सीन का नाम, वैक्सीन किन बीमारियों से बचाती है, इसकी जानकारी और सबसे पास के हेल्थ वर्कर से कॉन्टैक्ट करने की साफ़ अपील होती है।

यह पहल बिहेवियरल रिसर्च पर आधारित है और बेनिफिशियरी को हेल्थ से जुड़े फैसले लेने के लिए एक्टिवेली

में भी यही नतीजे मिले। SMS मैसैज से परेंट्स की हेल्थ की जानकारी बढ़ी है और वे वैक्सीनेशन के लिए समय पर हेल्थ सेंटर जाते हैं। महाराष्ट्र में सर्वे के नतीजे प्रोजेक्ट सुविता 2025 में परेंट्स और 2023 में ASHA वर्कर्स के बीच किए गए सर्वे में ये नतीजे सामने आए। 1,192 परेंट्स में से 70 परसेंट परेंट्स को सुविता से SMS मिलने की बात याद आई। इनमें से 48 परसेंट परेंट्स ने मैसैज का टॉपिक (वैक्सीनेशन या मेटरनल हेल्थ) सही बताया। 40 प्रतिशत बेनिफिशियरी ने कहा कि मैसैज बहुत काम का था, जबकि 5.6 प्रतिशत के लिए यह जानकारी का मुख्य सोर्स था। 90 ASHA वर्कर में से 61 प्रतिशत ने कहा कि SMS रिमाइंडर से बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन के लिए इकट्ठा करना आसान हो गया। इनमें से 36 ASHA वर्कर ने बताया कि कुछ माता-पिता सिर्फ इसलिए हेल्थ सेंटर आए क्योंकि उन्हें SMS मिला था।

मोटिवेट करती है। ग्लोबल रिसर्च (USA, केन्या, नाइजीरिया, वगैरह) के मुताबिक, SMS रिमाइंडर से बिना वैक्सीनेशन वाले बच्चों का परसेंटेज लगभग 15 परसेंट कम हुआ है। महाराष्ट्र में सुविता प्रोजेक्ट के एक सर्वे

मुंबई उपनगरीय जिले में मो हि मेस का उत्साह के साथ आगाज

वित्तीय क्षेत्र में ‘लावारिस संपत्ति निपटान’ अभियान नागरिकों के लिए उपयोगी - जिला कलेक्टर सौरभ कटियार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। वित्तीय क्षेत्र में ‘लावारिस संपत्ति निपटान’ अभियान न केवल वित्तीय क्षेत्र के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर सौरभ कटियार ने नागरिकों से इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की है। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के वित्तीय सेवा विभाग की सलाह के अनुसार, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) महाराष्ट्र और जिला अग्रणी बैंकों ने ‘लावारिस संपत्ति का निपटारा’ पहल के तहत शिविरों का आयोजन किया है। मुंबई उपनगर में शिविर का उद्घाटन जिला कलेक्टर सौरभ कटियार ने उत्तर भारतीय संघ हॉल, बांद्रा (पूर्व) में किया, जहाँ वे बोल रहे थे। इस मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर

पुनीत पंचोली, केनरा बैंक के चीफ जनरल मैनेजर रणजीव कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर सुनील कुमार शर्मा, यूको बैंक के जनरल मैनेजर संदीप कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर उत्तम कुमार वगैरह मौजूद थे। इस पहल का मकसद अलग-अलग बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स में जमा रकम, शेयर, डिविडेंड, इश्योरेंस पॉलिसी, प्रोविडेंट फंड (इड) जैसी लंबे समय से बेकार या बिना प्रोसेसिंग-किताब वाली संपत्तियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और सही लाभार्थियों को जानकारी देना है। यह कैंपेन मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रिजर्व बैंक और सभी शामिल बैंकों के मिले-जुले प्रयासों से बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा।

इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कटियार ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों के कस्टमर्स को बैंक डिपॉजिट

ट्रांज़ेक्शन प्रोसेस के बारे में पता नहीं है। अक्सर जानकारी के अभाव या प्रोसेस की जानकारी न होने की वजह से बैंकों में अकाउंट होल्डर्स का बेकार पैसा इस्तेमाल नहीं हो पाता। यह कैंपेन कस्टमर्स को आसानी से उपलब्ध कराने के बड़े मकसद से लागू किया जा रहा है। बैंक अकाउंट प्रोसेस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह कैंपेन अक्टूबर से शुरू किया गया है और ये कैंपेन इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि कस्टमर्स का बिना क्लेम वाला पैसा उन्हें अक्टूबर से शुरू किया गया है और ये कैंपेन दिसंबर तक लगाए जाएंगे। इसके ज़रिए कस्टमर्स के अकाउंट में मौजूद पैसे उन्हें दिए जा सकेंगे। इसमें बैंक का रोल अहम है और यह पहल नागरिकों को उनके बैंक अकाउंट में बकाया रकम दिलाने में मददगार होगी। इस कैंप में हिस्सा लेकर वे अपने या अपने परिवार के सदस्यों के बिना बताए गए डिपॉजिट और फाइनेंशियल एसेट्स की जांच करें और रिजर्व बैंक क्लेम जमा करें। इस कैंप में बैंक के सीनियर अधिकारी, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि

और संबंधित संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन जिला कलेक्टर ने बैंक कस्टमर्स से इस मौके का फायदा उठाने और इस कैंपेन को सफल बनाने की अपील की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर पुनीत पंचोली ने कहा कि यह कैंपेन इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि कस्टमर्स का बिना क्लेम वाला पैसा उन्हें वापस मिल सके। चूंकि कई अकाउंट कैंप दिसंबर तक लगाए जाएंगे। इसके अलावे बैंक को इन अकाउंट्स में संबंधित लोगों को उनका पैसा वापस करने में मुश्किल हो रही है। इस वजह से अकाउंट होल्डर को पैसा वापस नहीं किया जा सकता। हालांकि, खाताधारकों को सभी संबंधित जानकारी, नामांकन आदि को पूरा करने के लिए सावधान रहना चाहिए। उदम पोर्टल खाताधारकों की सुविधा के लिए बहुत उपयोगी है और उनके वर्तमान और पुराने खातों के बारे में जानकारी

प्रदान करता है, इसका लाभ उठाएं। सभी खाताधारकों को अपने बैंक खातों को सक्रिय रखना चाहिए, समय-समय पर अपने केवाईसी, संपर्क नंबर, पते का विवरण अपडेट करना चाहिए। अपने खाते के लेन-देन के बारे में सतर्क रहें। इसके लिए, बैंकों को प्राहकों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना चाहिए, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए इस पहल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, पंचोली ने कहा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, नागरिकों को वित्तीय दावों की प्रक्रिया के बारे में सूचित करना और विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा बेकार धन को लाभार्थियों तक पहुंचाना है।

इस अभियान में नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। लंबे समय से खाते में पड़ी लावारिस संपत्ति को वापस पाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन

देकर कई लोगों की सीधे मदद की गई। अपनी राशि के बारे में जानकारी लेने, उसे सत्यापित करने और प्रक्रिया को समझने के लिए कार्यक्रम स्थल पर, वित्ति विभिन्न बैंकों के अलग-अलग स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉल्स के ज़रिए, लोग अपने पुराने या बंद पड़े अकाउंट्स की तुरंत जांच कर सकते थे, इश्योरेंस पॉलिसी, फिक्स्ड डिपॉजिट, इइ या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से जुड़ी जानकारी, क्लेम के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर गाइडेंस पा सकते थे, और सीधे संबंधित बैंक के अधिकारियों से बातचीत कर सकते थे। इस मौके पर, बेनिफिशियरी कस्टमर्स को एक्टिवेशन सर्टिफिकेट दिए गए। साथ ही, फाइनेंशियल सेक्टर में क्लेम के विषय पर एक किताब भी रिलीज़ की गई। इस मौके पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लीडिंग डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कांतिलाल बाविस्कर ने धन्यवाद दिया।

स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए 6 और 7 दिसंबर को ग्लोबल यूथ फेस्टिवल 2025

मुंबई। स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट ने श्रीमद राजचंद्र मिशन के साथ मिलकर 6 और 7 दिसंबर को शहर के युवाओं के लिए बांद्रा के जियो वर्ल्ड गार्डन में ग्लोबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया है। यह फंक्शन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर एडवोकेट माणिकराव कोकाटे की मौजूदगी में होगा। इसमें 10,000 से ज़्यादा युवा मन की शांति, एडवेंचर, आर्ट्स, कल्चर, म्यूज़िक, योग-मेडिटेशन, कम्युनिटी से जुड़ी एक्टिविटीज़ और (स्किल-बिल्डिंग) स्किल डेवलपमेंट जैसी खास एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर यह देश का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल होगा। यह फेस्टिवल खुद को बदलकर समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं का एक मूवमेंट बनेगा। लंदन और पुणे जैसे शहरों के बाद इस साल ग्लोबल यूथ फेस्टिवल मुंबई में हो रहा है। ग्लोबल यूथ कम्युनिटी 20 से ज़्यादा देशों और 170 शहरों में फैले युवाओं का एक प्रेरणा देने वाला मूवमेंट है। क्रिएटिव, प्रोफेशनल्स,

आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स और चेंजमेकर्स ग्लोबल यूथ कमेटी बनाने के लिए एक साथ आए हैं। हजारों लोगों को एक साथ लाने वाली साइकिलथॉन जैसी एक्टिविटीज़, रूरल डेवलपमेंट के लिए कई प्रोजेक्ट्स, और हेल्थ, एनिमल वेलफेयर, और एजुकेशन के लिए इनिशिएटिव्स के साथ, यह फेस्टिवल सिर्फ़ एंटरटेनमेंट का सेलिब्रेशन नहीं होगा, बल्कि इम्पैक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन का भी सेलिब्रेशन होगा। म्यूज़िक या आर्ट जैसी किसी एक थीम तक लिमिटेड होने के बजाय, ग्लोबल यूथ फेस्टिवल एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस है। इसमें विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, एनिमल वेलफेयर, एनवायरनमेंटल कंज़र्वेशन, देश का सबसे बड़ा आउटडोर साउंड हीलिंग एक्सपीरियंस, और म्यूज़िक, आर्ट, मेडिटेशन, जर्नलिंग, पॉटरी, ड्रम सर्कल्स, वगैरह जैसी मज़ेदार पॉप-अप एक्टिविटीज़ जैसे सोशल कॉज़ दिखाए जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया youthfestival.srmd.org पर जाएं।

हिंदू खटिक समाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। हिंदू खटिक समाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडियरी) एप्लीकेंट्स को बिज़नेस शुरू करने के लिए ग्रांट स्कीम, सीड कैपिटल स्कीम, डायरेक्ट लोन स्कीम और NSFDC स्कीम चला रही है। कॉर्पोरेशन के मुंबई शहर और सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने हिंदू खटिक कैंटेगरी के अनुसूचित जाति के बेनिफिशियरीज़ से फाइनेंशियल इयर 2025-26 का टारगेट पाने के लिए इन स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की है। ग्रांट स्कीम - इस स्कीम की प्रोजेक्ट लिमिट Rs. 50,000 है और प्रोजेक्ट लिमिट का 50 परसेंट या ज़्यादा से ज़्यादा Rs. 25,000 ग्रांट के तौर पर दिया जाता है और बाकी रकम बैंक के ज़रिए दी जाती है। बैंक लोन पर बैंक के नियमों के हिसाब से इंटरसेट लगता है। लोन आम तौर पर तीन साल के

अंदर चुकाना होता है। सीड कैपिटल स्कीम - इस स्कीम की प्रोजेक्ट लिमिट Rs. 50,001 से Rs. 10,000 तक है। सीड कैपिटल लोन कॉर्पोरेशन द्वारा 5 लाख और प्रोजेक्ट लिमिट का 20 परसेंट चार परसेंट की ब्याज दर पर दिया जाता है। इस रकम में कॉर्पोरेशन की तरफ से प्रोजेक्ट लिमिट का 50 परसेंट या ज़्यादा से ज़्यादा Rs. 50 हजार की ग्रांट शामिल है। बैंक लोन 75 परसेंट पर दिया जाता है और इस लोन पर ब्याज दर बैंक के नियमों के हिसाब से लगती है। कॉर्पोरेशन और बैंक लोन को एक ही समय में तीन से पांच साल के अंदर बराबर महीने की किश्तों में चुकाना होता है। आवेदक को अपना पांच परसेंट हिस्सा देना होता है। डायरेक्ट लोन स्कीम - इस स्कीम की प्रोजेक्ट लिमिट Rs. 1 लाख तक है और लोन की रकम प्रोजेक्ट लिमिट का 50 परसेंट या ज़्यादा Rs. 50 हजार तक है। ग्रांट दिया जाता है और बाकी Rs. 50 हजार की रकम कॉर्पोरेशन के ज़रिए चार परसेंट सालाना ब्याज दर पर दी जाती है। लोन आम तौर पर तीन साल

के अंदर चुकाना होता है। एनएसएफडीसी योजना - परियोजना की सीमा 1 लाख 40 हजार से 2 लाख तक है तथा कुल परियोजना का 90 प्रतिशत एनएसएफडीसी, नई दिल्ली के माध्यम से प्राप्त होता है। हालांकि, अधिकतम 50 हजार का अनुदान है। और शेष राशि बीज पूंजी के रूप में दी जाती है।इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड

यह है कि आवेदक अनुसूचित जातियों की हिंदू खटिक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राज्य निगम योजना के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय सीमा रुपये 3 लाख है। आवेदक किसी भी निगम योजना (राज्य/केंद्र) का बकायादार नहीं होना चाहिए।

बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए डी-डुलीकेशन टेक्नोलॉजी अपनाने की ज़रूरत है- डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आंचल गोयल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ पहल इनएक्टिव अकाउंट्स में जमा पैसे को बिना किसी मदद के संबंधित अकाउंट होल्डर्स और उनके वारिसों तक वापस पहुंचाने के लिए उपयोगी है और सभी बैंकों को इस पहल के बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए। साथ ही, बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, सभी बैंकों के छह डिपार्टमेंट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया की तर्ज पर डी-डुलीकेशन टेक्नोलॉजी अपनाने की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आंचल गोयल ने कहा। मुंबई शहर जिले में अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी के डिस्पोज़ल पर जिले के लीडिंग बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित एक कैंप का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आंचल गोयल ने किया। इस मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर पुनीत पंचोली, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के जनरल मैनेजर सुनील शर्मा, केनरा बैंक के चीफ जनरल मैनेजर रंजीव कुमार, बैंक

अर्थोरिटी के तौर पर काम करेंगे। आपके ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटबिलिटी बनाए रखना ज़रूरी है। राहुल पांडे ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फंड, MLA फंड और अलग-अलग सरकारी स्कीमों को लागू करते समय ट्रांसपेरेंसी अपनाना ज़रूरी है। जनता का भरोसा बनाए रखना गुड गवर्नंस की पहचान है, और इन्फॉर्मेशन कमीशन का काम नागरिकों और सरकार के बीच बातचीत को मज़बूत करना है। यह कहते हुए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने के बहुत अच्छे मकसद को पूरा कर रहा है, पांडे ने यह भी कहा कि कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग जैसी पहलों को बढ़ावा दिया गया है ताकि सरकार का कामकाज ज़्यादा खुला और ट्रांसपेरेंट हो सके। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर श्री पांडे ने यह भी कहा कि सामाजिक असमानता को देखते हुए कानूनों को रियलिस्टिक नज़रिए से लागू करना ज़रूरी है।

नए क्रिमिनल कानूनों पर एरिज़बिशन को अचानक मिला रिस्पॉन्स

मुंबई। इंडियन पीनल कोड, इंडियन सिविल सिक्वोरिटी कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के नए क्रिमिनल कानूनों पर आधारित एक एरिज़बिशन आज़ाद मैदान में लगाई गई है। इस एरिज़बिशन में 25 मिनट के ड्रामा डेमोंस्ट्रेशन के ज़रिए नए कानूनों को डिटेल में समझाया गया है। इस अलग-अलग तरह की एरिज़बिशन को लोगों से अचानक मिला रिस्पॉन्स मिल रहा है। यह एरिज़बिशन रविवार, 23 नवंबर, 2025 तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। एरिज़बिशन में मेन कंट्रोल रूम, पुलिस स्टेशन, डायरेक्टरेट ऑफ़ ज्यूडिशियल असिस्टेंट लैबोरेटरीज, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ़ प्रोसिक्यूशन, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट और सेट्रल जेल के हॉल हैं। इस नए कानून की धाराओं के हिसाब से आरोपियों को सज़ा देने का तरीका डेमोंस्ट्रेशन के ज़रिए दिखाया गया है। एरिज़बिशन में अलग-अलग धाराओं की जानकारी वाले पोस्टर आकर्षक कलर स्कीम में दिखाए गए हैं। एरिज़बिशन में सिर्फ़ प्रेजेंटेशन ही नहीं है, बल्कि कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए दो मिनट के 10 सवाल वाले डिजिटल क्वेश्चनेयर वाली स्क्रीन भी हैं। इन स्क्रीन पर नागरिक सवालों के जवाब दे रहे हैं और इस कानून के बारे में और जान रहे हैं। एरिज़बिशन पर डिजिटल फॉर्म में जवाब देने का भी इंतज़ाम किया गया है। जेलों में कैदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स के स्टॉल भी हैं।

मुंबई हवाई अड्डे पर 53 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ, सोना, हीरे जब््त, 20 लोग गिरफ्तार

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने पिछले सप्ताह विभिन्न अभियानों में 53 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के हाइड्रोपोनिक गांजा, सोना और हीरे जब््त किये और इस सिलसिले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि ये बरामदगियां 13 से 20 नवंबर के बीच विभिन्न अभियानों के दौरान की गईं। अभियान के पहले भाग में अधिकारियों ने सात अलग-अलग मामलों में 25,318 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक गांजा



इस सिलसिले में सात यात्रियों को गिरफ्तार किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि अन्य अभियानों में, सात मामलों में 26.981 करोड़ रुपये मूल्य का 26.981 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया और इन मामलों में आठ यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ के अलावा, इसी अवधि में सोने की तस्करी के चार मामलों का पता लगाया गया और चार यात्रियों के

कब्जे से कुल 551 ग्राम 24 कैरट सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत 65.57 लाख रुपये है। एक अन्य मामले में, सीमा शुल्क अधिकारियों ने 469.75 कैरट हीरे जब््त किए, जिनमें 43.5 कैरट प्राकृतिक और 426.25 कैरट कृत्रिम हीरे शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 54.13 लाख रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि कीमती सामान यात्री ने अपने शरीर में छुपा रखा था और उसे व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। अधिकारी ने बताया कि मामले में जांच जारी है।



मिशन-2026 : माओवादी आतंक का खात्मा तय

देश सहित छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। छत्तीसगढ़ का कुख्यात माओवादी आतंकी हिडमा 18 नवंबर को मारा गया। छत्तीसगढ़-आंध्रप्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षाबलों ने हिडमा की पत्नी समेत कुल 6 नक्सली-माओवादियों को ढेर कर दिया है।

वस्तुतः नक्सलवाद-माओवाद के पीछे केन्द्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है।जो सरेंडर करने वालों का स्वागत भी कर रही है। पुनर्वास भी सुनिश्चित कर रही है। लेकिन अगर माओवादी, आतंक का रास्ता नहीं छोड़ते तो उनका अंत भी तय है। यानी मिशन-2026 पूरी तरह से एक्टिवेट है।

17 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रामनाथ गोयनका व्याख्यान में भी माओवादी आतंक की समाप्ति का जिक्र किया। अर्बन नक्सलियों और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि - 'पूरे देश में नक्सलवाद-माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। आप भी जानते हैं, बीते पांच दशकों तक देश का करीब-करीब हर बड़ा राज्य, माओवादी आतंक की चपेट में, चपेट में रहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती-पोसती रही और सिर्फ दूर-दराज के क्षेत्रों में जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद-पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी-बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया है।'

साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी गंभीरता के साथ देश की एकता पर गंभीर खतरे को भी चिन्हांकित किया। उन्होंने कहा कि - '10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली, माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी- माओवादी कांग्रेस, रश्प बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि ये मुस्लिम लीगी- माओवादी कांग्रेस, अपने स्वार्थ में देशहित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी- माओवादी कांग्रेस, देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है।'

यानी संदेश साफ है कि नक्सलवाद-माओवाद के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति तय है। मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद-माओवाद का संपूर्ण खात्मा सुनिश्चित है। ये अभियान अपने अंतिम चरण पर है। साथ ही नक्सलवाद-माओवाद को पालने-पोसने वालों और समर्थकों के लिए कड़ी चेतावनी है। अगर देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा से खेलेंगे तो अंजाम बुरा होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजयशर्मा जिस तरह से नक्सलवाद-माओवाद के उन्मूलन में मिशन मोड में लगे हैं। वो काबिले तारीफ है। माओवादी हिडमा के मारे जाने के पहले विजय शर्मा उसके बांग पूवर्तौ गए थे। हिडमा की मां के साथ भोजन किया था। प्रशस्त रूप में उनका आदर सत्कार किया था। हिडमा की मां से सरेंडर करवाने के लिए अपील भी करवाई थी। इसके बाद जब हिडमा ने सरेंडर नहीं किया तो सुरक्षाबलों ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया।

2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की वापसी होने के बाद बस्तर क्षेत्र से माओवादियों का खात्मा हो रहा है। व्यापक स्तर पर आत्मसमर्पण करया जा रहा है। पहले 'बोली' फिर 'गोली' दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। स्थायी शांति की ओर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चेताया है चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। माओवादियों का 'अर्बन' मॉडल जिसे 'अर्बन नक्सली' के नाम से जाना जाता है। वो अभी भी देश भर में सक्रिय हैं। नई रणनीतियों पर लगा हुआ है। लेकिन ये तय है कि देश भर से नक्सलवाद-माओवादी आतंकवाद का खात्मा होगा। अर्बन नक्सलियों के ताबूत में भी अंतिम कोल ठोंकी जाएगी। स्थायी शान्ति और विकास की बहाली होगी। ये नया भारत है। जो अपने नागरिकों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संदेश साफ है देशविरोधी कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।



शोर-शराबे का दौर, खोती हुई आवाजें, क्या हम ठहरकर खुद को देख पाएंगे? गैजेट्स के बीच अकेला इंसान

हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है, लेकिन इस बदलाव की गति ने हमारी चेतना को लगभग सुन्न कर दिया है। खबरें आती हैं, हिलाती हैं और अगले ही पल किसी और सनसनी के नीचे दब जाती हैं। इस तेजी से भागती दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है ठहराव, और शायद सबसे जरूरी भी।

देश में चुनावी शोर होता ही रहता है। हर गली-कूचे में नारों की गुंज, मीडिया में बहसों की गरमी, सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप की झड़ी लगी रहती है। लेकिन अगर हम इन आवाजों के बीच कुछ देर चुप बैठकर सोचें, तो पाएंगे कि आम आदमी की आवाज कहीं खो-सी गई है। वास्तव में जिसे लोकतंत्र का केंद्र होना चाहिए, वही सबसे हाशिये पर है।

गांवों में पानी नहीं है, शहरों में हवा नहीं है, किसान आज भी कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहे हैं और युवा बेरोजगारी के दुश्चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन चुनावी बहसें मंदिर-मस्जिद, जाति-धर्म, राष्ट्रवाद और विरोधियों की गालियों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। हम जैसे देखना ही भूल गए हैं कि राजनीति का मतलब लोगों की जिंदगी बेहतर करना है।

इस सबके बीच, ऐसा लगता और दिखता है कि तकनीक ने हमारी दुनिया को व्यापक स्तर पर जोड़ा है। मगर सच्चाई यह है कि तकनीकी दुनिया का विस्तार जैसे-



जैसे होता गया है, उतना ही हम अलग-थलग भी हुए हैं। हम घंटों मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी के स्क्रीन पर टिके रहते हैं, लेकिन पास बैठे लोगों से आंख मिलाने का हमारे पास वक्त नहीं होता।

हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष तकनीकी और जैव तकनीकी के युग में हैं, लेकिन मनुष्यता का सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वहीं है

- सहानुभूति। सवाल है कि क्या हम एक-दूसरे के दुख को महसूस करना भूल गए हैं?

दिल्ली की किसी झुग्गी में बैठी एक मां, जो दिन भर घरों में झाड़ू-

कभी-कभी लगता है कि जैसे हम एक बड़े भ्रम में जी रहे हैं। एक विकासशील देश होने का भ्रम, एक महान संस्कृति के वाहक होने का भ्रम, एक विश्वगुरु बनने की



पोंछा कर अपना पेट पालती है, आज महंगाई की मार से दो जून की रोटी भी मुश्किल से जुटा पा रही है। उसकी पीड़ा और अभाव

की हालत किसी 'विकास दर' में दर्ज नहीं होती। न ही वह किसी आधुनिक और मशहूर ट्रैन की तस्वीर में शामिल है। मगर अगर भारत वहीं सांस लेता है - गर्मी के मौसम की झुलसती दोपहर में, टूटी हुई चप्पलों के साथ।

आकांक्षा का भ्रम, लेकिन क्या हमने अपने भीतर झांककर देखा है?

सार्वजनिक रूप से भी बोली जाने वाली हमारी भाषा कितनी आक्रामक हो गई है। असहमति का मतलब दुश्मनी, आलोचना का मतलब राष्ट्रद्रोह और सवाल पूछने का मतलब साजिश बन गया दिखता है। यह केवल भारत की कहानी नहीं है। पूरी दुनिया जैसे किसी अस्थायी असंतुलन से गुजर

दिल्ली दिलवालों की ही नहीं, अब 'फेफड़े वालों' की भी नहीं रही?

हर साल नवंबर का महीना आते ही देश की राजधानी दिल्ली एक 'गैस चैंबर' में तब्दील हो जाती है। नवंबर 2025 में एक बार फिर दिल्लीवासियों का सांस लेना दूभर हो गया है। सुबह की शुरुआत ताजी हवा से नहीं, बल्कि धुंध की एक मोटी चादर और आंखों में जलन के साथ हो रही है। लगातार गिरती वायु गुणवत्ता को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों ने इसे 'मेडिकल इमरजेंसी' करार दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली का प्रदूषण अब केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि लोक स्वास्थ्य का बड़ा खतरा बन गया है।

वर्तमान स्थिति के ताजा आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 के मध्य में दिल्ली के कई इलाकों (जैसे बवाना, वजीरपुर, और जहांगीरपुरी) में एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया है। कुछ स्थानों पर यह 500 के खतरनाक स्तर को भी छू रहा है। स्थिति को देखते हुए 'प्रेम' के कड़े चरण लागू किए गए हैं, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक और बी एस-3 पेट्रोल व बी एस -4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध शामिल हैं।परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक समाधान का समर्थन

करते हुए, ग्रेडेड रिसपांस एक्शन प्लान के तहत प्रतिबंधित सभी गतिविधियों पर साल भर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को दोनों राज्यों में पराली जलाने के मुद्दे पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा।

एक्यूआई बताता है कि हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। जब एक्यूआई 0 से 50 के बीच होता है, तब हवा अच्छी मानी जाती है और सेहत पर कोई असर नहीं होता। 51 से 100 के बीच हवा संतोषजनक होती है, जिससे बहुत संवेदनशील लोगों को थोड़ा सांस लेने में परेशानी हो सकती है। 101 से 200 के बीच हवा मध्यम होती है, जो फेफड़ों, अस्थमा या हृदय की बीमारी वाले लोगों को दिक्कत दे सकती है। 201 से 300 तक की हवा खराब होती है और लंबे समय तक इंसानें रहने से अधिकतर लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है।301 से 400 के बीच हवा बहुत खराब होती है, जिससे लोगों को सांस की बीमारियां हो सकती हैं। जब एक्यूआई का लेवल 400 के पार पहुंच जाता है, जैसा कि इन दिनों हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 के सूक्ष्म कणों की मात्रा इतनी ज्यादा

है कि ये फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। एक्सपर्ट का साफ अनुमान है कि ऐसे गंभीर प्रदूषण में बिना मास्क के बाहर निकलना या साँस लेना, एक दिन में 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर हो

बढ़ा रहे हैं।बढ़ते प्रदूषण की वजह से रोजाना 20 से 30 मरीज सांस और अन्य प्रदूषणजनित बीमारियों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। हवा में मौजूद अल्ट्रा-फाइन कण गर्भवती महिलाओं के शरीर के



सकता है।जो स्वस्थ लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है और बीमार लोगों की हालत और बिगाड़ सकती है।

एम्स के विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण अब केवल अस्थमा, सांस फूलना और सीओपीडी तक सीमित नहीं है। हवा में मौजूद महीन कण रक्तप्रवाह में शामिल होकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम भी

माध्यम से गर्भस्थ शिशु तक पहुंच रहे हैं। इससे न केवल भ्रूण की वृद्धि प्रभावित होती है बल्कि कम वजन वाले बच्चों के जन्म और आगे चलकर फेफड़ों के कमजोर होने की आशंका भी बढ़ जाती है।

हाल ही में, एक प्रतिष्ठित भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर

स्थिति और अपने छोटे बेटे के स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी गुप 'ए' सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बढ़ते प्रदूषण के संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद

इतना बढ़ जाए कि वह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगे, तो यह सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाल ही में जंतर मंतर पर आइए सांस लें नामक एक विरोध प्रदर्शन किया गया। जिसमें आइए सांस लें केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता को भी दर्शा रहा था। लोग इस बात से नाराज हैं कि प्रदूषण उन्हें इसी जानलेवा स्थिति का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये गुस्सा इस मांग पर केंद्रित है कि स्वच्छ हवा को स्वास्थ्य के अधिकार के रूप में देखा जाए।

दिल्ली का प्रदूषण अब एक मौसमी समस्या नहीं, बल्कि एक साल भर रहने वाला संकट बन रहा है जो सदियों में जानलेवा हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि साफ हवा हमारा अधिकार ही नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी जरूरत है। यदि आज हमने कड़े कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए दिल्ली रहने लायक शहर नहीं बचेगा। यह समय 'चिंता' करने का नहीं, बल्कि 'चिंतन' और 'कार्रवाई' का है। आज की जहरीली हवा, कल की गंभीर बीमारी है। 'मुस्कुराइये कि आप दिल्ली में' हैं, पर जरा ध्यान रखिये, ये कोहरा नहीं, आपके फेफड़ों का इम्तिहान है।'

गाजा में ट्रंप के प्लान को अमेरिका की मंजूरी मुस्लिम देशों का रुख देख अमेरिका के सामने पीछे हटे चीन-रूस

गाजा शांति समझौते को लेकर अमेरिका अपनी पीठ थपथपाते में जुटा हुआ है। लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो रुक-रुक कर गाजा पर हमले करता जा रहा है। अक्टूबर महीने के आखिर में इजराइल के हमले में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। दरअसल गाजा शांति समझौता उस संघर्ष को रोकने के लिए हुआ जिसमें 67, 000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई। 19 लाख लोग बेघर हो गए। इजराइली हमले में गाजा का 80इ हिस्सा तबाह हो गया। बात 7 अक्टूबर 2023 की सुबह की है। हमास लड़ाकों ने इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र पर हमला कर दिया। हमास आतंकियों ने सुपरनोवा फेस्टिवल को निशाना बनाया जिसमें करीब 1200 इजराइलियों की मौत हो गई। जबकि 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। उस हमले के बाद हमास को खत्म करने के मकसद से इजराइल ने आर-पार की लड़ाई शुरू की। आज आपको बता देते हैं कि क्या गाजा शांति प्रस्ताव से दशकों पुराना विवाद सुलझ जाएगा? यूएन से मिली हरी झंडी के बाद हमास

को क्या ये कबूल होगा। संयुक्त राष्ट्र में आखिर वीटो वाले चीन और रूस ने क्यों वॉकआउट का रास्ता चुना।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा मुद्दे पर ट्रंप के प्रस्ताव को मंजूरी देकर मध्य पूर्व में एक और शांति को ना सिर्फ मजबूती दी बल्कि आम फिलिस्तीनियों को अब तक की सबसे बड़ी राहत पहुंचाई। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद अब गाजा में अंतरराष्ट्रीय बल भेजने का रास्ता साफ हो गया। जिसके बाद युद्ध से तबाह हुए इलाकों में शांति और मानवीय मदद आने लगेगी। हालांकि इस पर कोई समय सीमा या फिर शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं।

ट्रंप ने सितंबर में 20 पॉइंट का अपना यह प्लान जारी किया था। इसमें गाजा को आतंकवाद

मुक्त और स्थिर क्षेत्र के रूप में विकसित करने का टारगेट रखा गया था। गाजा के पुनर्निर्माण और शासन के लिए बोर्ड ऑफ पीस नाम की एक इंटरनैशनल संस्था बनाने का भी जिक्र है। इस प्रस्ताव में इंटरनैशनल सैनिकों की तैनाती, सीजफायर और शासन आदि के रोडमैप का जिक्र है। गाजा के लिए एक स्पेशल फोर्स इंटरनैशनल स्टैबलाइजेशन फोर्स के गठन की भी बात है।गाजा के शासन की कमान एक अंतरराष्ट्रीय निकाय बोर्ड ऑफ पीस (बीओपी) के हाथ में रहेगी। इस बोर्ड के डायरेक्टर खुद ट्रंप होंगे। ट्रंप का गाजा प्लान सिर्फ शांति नहीं, रियल एस्टेट का बड़ा मौका है। दामाद जेरेंड कुश्नर ने 2024 में कहा था कि गाजा की समुद्री पट्टी 'बहुत कीमती हो सकती है। उनकी फर्म एफिनटी पार्टनर्स को सऊदी अरब से 16, 800 करोड़ रु. मिले हैं। गाजा पुनर्निर्माण में प्राइवेट सेक्टर को 30 साल की टैक्स छूट और जमीन के अधिकार मिलेंगे। ट्रंप खुद बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन बनकर नियंत्रण रखेंगे। इवांका, डोनाल्ड जुनियर और एरिक के ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खाड़ी देशों में

प्रोजेक्ट हैं। विशेषज्ञ इसे ट्रंप परिवार का भारी कॉम्प्लेक्ट ऑफ इंटररेस्ट बता रहे हैं।

गाजा पट्टी की चौड़ाई औसतन 8 से 10 किमी है उत्तर में यह 6 किमी जबकि दक्षिण में 12 किमी तक चौड़ी है। अमेरिकी योजना के मुताबिक गाजा को दो मुख्य हिस्सों ग्रीन जोन और रेड जोनमें बांटने का प्रस्ताव है। दोनों हिस्से लगभग 4-4 किमी के माने जा रहे हैं। इनके बीच करीब 1 किमी का बफर/थेलो जोन होगा, जहां इंटरनैशनल स्टैबलाइजेशन फोर्स (आईएसएफ) की तैनाती होगी। ग्रीन जोन में निर्माण कार्य होगा जबकि 23 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रेड जोन में रहने को



मजबूर होंगे। गाजा में इंटरनैशनल स्टैबलाइजेशन फोर्स के 10 से 15 हजार सैनिक तैनात होंगे। इंडोनेशिया, अजरबैजान, पाकिस्तान, मिस्त्र व यूएई जैसे मुस्लिम देश सैनिक भेज सकते हैं।

हमास ने सुरक्षा परिषद के इस फैसले को खारिज कर दिया है। हमास ने कहा कि यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के अधिकारों और मागो को पूरा करने में विफल और गाजा पर एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास थोपने का प्रयास करता है। हमास ने विशेष रूप से स्थिरीकरण बल को सशस्त्र समूहों को निष्क्रिय करने का निर्देश देने वाले प्रावधानो की तीखी आलोचना की। न्यूज

एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, हमास ने कहा-अंतर्राष्ट्रीय फोर्सें को गाजा पट्टी के अंदर कार्य और भूमिकाएं सौंपना, इसकी तटस्थता को समाप्त करता है।

यूरोपीय देश और अमेरिका के करीबी समझे जाने वाले अरब मुल्क अगर आगे भी इसी तरह सक्रिय रहें तो 'बोर्ड ऑफ पीस' और 'इंटरनेशनल स्टैबिलाइजेशन फोर्स', दोनों को इसाइल की जेबी संस्था बनने से रोका जा सकता है। विश्व बैंक यूएन के मुताबिक गाजा की पुनर्विकास की अनुमानित लागत करीब 5.8 लाख करोड़ रुपए है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मित्र जैसे देश ट्रंप प्लान को समर्थन दे रहे हैं, बदले में इजराइल से संबंध सामान्य करना और ईरान के खिलाफ मजबूत गठबंधन चाहते हैं। गाजा पुनर्निर्माण मं ये देश सैनिक भी भेजेंगे ताकि हमास पूरी तरह खत्म हो। सऊदी अरब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन के लिए गाजा फंडिंग का इस्तेमाल कर रहा है। यूएई हमास को खतरा मानता है, कतर क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ये देश बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर गाजा शासन में हिस्सा लेंगे, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य की स्पष्ट

गारंटी मांग रहे हैं। हैं। प्राइवेट कंपनियों को 30 साल टैक्स छूट, लैंड राइट्स और ट्रेड हब का लाभ मिलेगा।

सबसे दिलचस्प भूमिका पाकिस्तान की रही। जो मुस्लिम देश होने के चलते आमतौर पर फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहने का दावा करता है लेकिन पाक ने अमेरिकी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया और अब गाजा में तैनात होने वाली इंटरनेशनल स्टैबिलाइजेशन फोर्स के लिए सैनिक भेजने पर भी सहमत हो गया है। अनुमान है कि पाकिस्तान 1, 500 से 2, 000 सैनिक तक भेज सकता है। प्रस्ताव पास होते ही ट्रंप ने इसे 'गाजा में शांति की नई शुरुआत' बताया और पाकिस्तान की ओर दुश्पारा करते हुए कहा कि जो देश आगे आएंगे, वे भविष्य के बोर्ड ऑफ पीस में महत्वपूर्ण भागीदार होंगे।

ट्रंप के उस 20 सूत्रीय योजना को शामिल कर लिया गया जिस पर कभी रूस और चीन ने विरोध जताया था। लेकिन अरब सहित कई मुस्लिम देशों के रुख को देखकर दोनों देशों ने प्रस्ताव पर वीटो करने से परहेज किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में शांति, सुरक्षा और पुनर्निर्माण को लेकर गह्र महत्वपूर्ण

नहीं है। यह रोजमर्रा की भागीदारी, सवाल करने की संस्कृति और जवाबदेही की मांग से ही जीवित रहता है। और अगर हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे, तो इतिहास गवाह है कि सत्ताएं धीरे-धीरे नागरिकों के मुंह बंद करना जानती हैं।

दिमाग उग्र से नहीं, जिज्ञासा न होने से बूढ़ा होता है, सक्रिय सोच कैसे मस्तिष्क को जीवनभर युवा बनाए रखती है इसलिए जरूरी है कि हम ठहरें और देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। क्या हम वाकई बेहतर हो रहे हैं या बस बेहतर दिखने की कोशिश में लगे हैं? देश से लेकर दुनिया भर में आंकड़ों का जो चकाचौंध परोसा जा रहा है, क्या वह जमीनी स्तर पर भी वास्तव में अपनी तेज जितना ही प्रभाव दिखा पा रहा है?

दुनिया आगे जा रही है या कहीं कि आगे जाती हुई दिख रही है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि यह आगे बढ़ना किस दिशा में है। क्या दुनिया का 'आगे जाना' मानवीय मूल्यों के साथ है या फिर ये मूल्य पीछे छूट रहे हैं, नजरअंदाज किए जा रहे हैं या कहीं इसके विरुद्ध भी तो रास्ता नहीं तैयार किया जा रहा है? बिना मूल्यों के, बिना करुणा के, बिना आत्मनिरीक्षण के कोई भी प्रगति खोखली होती है। और खोखली इमारतें, चाहे कितनी भी ऊंची हों, एक दिन ढह जाती हैं। हम अभी भी संभल सकते हैं।

नहीं रही?

इतना बढ़ जाए कि वह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगे, तो यह सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाल ही में जंतर मंतर पर आइए सांस लें नामक एक विरोध प्रदर्शन किया गया। जिसमें आइए सांस लें केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि यह लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता को भी दर्शा रहा था। लोग इस बात से नाराज हैं कि प्रदूषण उन्हें इसी जानलेवा स्थिति का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये गुस्सा इस मांग पर केंद्रित है कि स्वच्छ हवा को स्वास्थ्य के अधिकार के रूप में देखा जाए।

दिल्ली का प्रदूषण अब एक मौसमी समस्या नहीं, बल्कि एक साल भर रहने वाला संकट बन रहा है जो सदियों में जानलेवा हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि साफ हवा हमारा अधिकार ही नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी जरूरत है। यदि आज हमने कड़े कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए दिल्ली रहने लायक शहर नहीं बचेगा। यह समय 'चिंता' करने का नहीं, बल्कि 'चिंतन' और 'कार्रवाई' का है। आज की जहरीली हवा, कल की गंभीर बीमारी है। 'मुस्कुराइये कि आप दिल्ली में' हैं, पर जरा ध्यान रखिये, ये कोहरा नहीं, आपके फेफड़ों का इम्तिहान है।'

कांग्रेस ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने से किया इनकार, कहा- कानून तोड़ने वालों के साथ नहीं

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हलचल के बीच कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह आगामी बुधन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी ने कहा कि वह उन संगठनों के साथ हाथ नहीं मिलाएगी जो कानून हाथ में लेते हैं या लोगों को डराते हैं। कांग्रेस के इस रुख के बाद विपक्षी खेमे में नई राजनीतिक दूरी और सियासी समीकरणों पर चर्चा तेज हो गई है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद यह फैसला लिया है कि वह बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लंबे समय से शरद पवार की अगुआई वाले एनसीपी (एसपी) के साथ साझेदारी रही है, लेकिन कानून तोड़ने वालों

से गठबंधन नहीं होगा। उनका यह बयान सीधे तौर पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे की ओर इशारा माना

मनसे नेता

कांग्रेस के इनकार के जवाब में मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि उनकी

के अनुसार, मनसे अपनी राजनीतिक रणनीति खुद तय करती है और उनकी पार्टी को किसी की मंजूरी



गया। कांग्रेस के रुख के बाद शिवसेना (यूबीटी) ने पार्टी को जल्दबाजी न करने और विपक्षी एकता बनाए रखने की सलाह दी थी।

हम स्वतंत्र, किसी पर निर्भर नहीं-

पार्टी किसी के दबाव में नहीं है और न ही महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। उन्होंने साफ कहा कि राज ठाकरे जो फैसला लेते हैं वही पार्टी का रुख होता है और कांग्रेस के बयान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देशपांडे

की जरूरत नहीं।

उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सतर्कता

कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग मनसे के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के खिलाफ है। पार्टी के नेताओं को

आशंका है कि यदि वे मनसे के साथ मंच साझा करते हैं, तो मुंबई में उनका उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। इसी कारण कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से गठबंधन की संभावनाओं को नकारते हुए कहा कि वह ऐसे दलों को अपने साथ नहीं रख सकती जो वर्षों से कानून को ताक पर रखकर राजनीति करते रहे हैं।

सवालों से बचती दिखाई वर्षा गायकवाड़

जब वर्षा गायकवाड़ से पूछा गया कि क्या शरद पवार कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और मनसे को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पवार का सभी दलों में सम्मान है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे किसी गठबंधन पर चर्चा नहीं की है। उन्होंने कहा कि काल्पनिक सवालों का कोई अर्थ नहीं। गायकवाड़ ने सुप्रिया सुले के उस बयान पर भी सीधे प्रतिक्रिया देने से बचा, जिसमें उन्होंने सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी।

शादी का झांसा देकर बांग्लादेशी महिलाओं ने व्यापारी से ठगे 1.08 लाख रुपये, तीन पर केस दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शांतिनगर पुलिस थाना क्षेत्र में शादी का प्रलोभन देकर एक व्यापारी से 1.08 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो बांग्लादेशी महिलाओं और एक पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस इसे संगठित अंतरराष्ट्रीय ठगी का मामला मानकर जांच कर रही है। शिकायतकर्ता, जो टेम्घर गांव, भिवंडी के निवासी हैं, ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक महिला का फोन आया था। महिला ने स्वयं को अविवाहित बताकर शादी की इच्छा जताई और विश्वास जीतकर बातचीत बढ़ाई। कुछ दिनों बाद उसने और उसके साथियों ने पीड़ित को यह कहकर रुपये भेजने के लिए राजी कर लिया कि शादी की प्रक्रिया

और आवश्यक कागजात तैयार कराने में खर्च आएगा। पीड़ित ने भरोसा कर कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शनों के माध्यम से कुल 1,08,700 रुपये भेज दिए। इसके बाद जब आरोपी संपर्क से गायब हो गए, तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शांतिनगर पुलिस ने गु. रंजि. क्र. 1276/2025 के तहत बीएनएस अधिनियम की धारा 318(4) और 3(5) में रिया सरकार (36), अरबिना दिदी (48) निवासी ढोलपुर, जिला बालुघाट (पश्चिम बंगाल) और रुस्मन कमलेश मंडल निवासी भिवंडी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों महिलाएं कथित तौर पर बांग्लादेश मूल की हैं। यह घटना 27 सितंबर 2025 की दोपहर में हुई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने शादी का लालच देकर सुनियोजित तरीके से व्यापारी को अपने जाल में फंसाया और रकम हड़प ली। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक उत्तम ओमासे कर रहे हैं।

बेलापुर और पनवेल के बीच विभिन्न इंजीनियरिंग कार्य हेतु शनिवार मध्यरात्रि से रविवार दोपहर तक विशेष ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल, पनवेल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 (डाउन हार्बर लाइन) के मुंबई एंड पर टर्नआउट को हटाने, शिफ्ट करने/स्लीविंग करने और लगाने के लिए 22.11.2025 (शनिवार) को 23.45 बजे से 23.11.2025 (रविवार) को 11.45 बजे तक बेलापुर और पनवेल के बीच अप और डाउन लाइनों पर विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक परिचालित करेगा।

ब्लॉक अवधि के दौरान उपनगरीय ट्रेनों का परिचालन:

ब्लॉक अवधि के दौरान बेलापुर और पनवेल स्टेशनों के बीच उपनगरीय सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी हार्बर लाइन पर अप और डाउन उपनगरीय सेवाएं बेलापुर / नेरुल / वाशी स्टेशनों पर शॉर्ट टर्मिनेट / ओरिजिनेट होंगी।इ ड्रांंस-हार्बर लाइन पर अप और डाउन सेवाएं ठाणे और नेरुल / वाशी स्टेशनों के बीच चलेंगी।

ट्रांस-हार्बर लाइन पर अप और डाउन सेवाएं ठाणे और नेरुल / वाशी स्टेशनों के बीच चलेंगी उपनगरीय ट्रेनों का कैंसलेशन / शॉर्ट टर्मिनेशन / ओरिजिनेशन निम्नानुसार होगा :

हार्बर लाइन दिनांक 23.11.2025 की ये डाउन लोकल सेवाएं कैंसल रहेंगी। पनवेल के लिए डाउन लोकल जो सीएसएमटी से 05.18 बजे, 07.26 बजे, 08.54 बजे, 10.10 बजे और 11.26 बजे प्रस्थान करती है । बेलापुर के लिए डाउन लोकल सेवाएं जो सीएसएमटी से 08.20 बजे, 08.58 बजे और वडाला रोड से 11.30 बजे प्रस्थान करती है । दिनांक 23.11.2025 की ये अप लोकल सेवाएं रह (कैंसिल) रहेंगी वाशी से 04.25 बजे निकलने वाली अप लोकल, बेलापुर से 06.22 बजे, 07.50 बजे, 08.06 बजे और 10.16 बजे निकलने वाली अप लोकल पनवेल से 06.57 बजे, 08.45 बजे और 10.21 बजे निकलने वाली अप लोकल डाउन उपनगरीय ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन दिनांक 22.11.2025 को 22.50 बजे सीएसएमटी से निकलने वाली पनवेल के लिए डाउन लोकल बेलापुर में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। अप उपनगरीय ट्रेनों का शॉर्ट ओरिजिनेशन पनवेल से 09.28 बजे और 11.28 बजे निकलने वाली अप लोकल वाशी से शॉर्ट ओरिजिनेशन होगी

पनवेल से 11.52 बजे निकलने वाली अप लोकल बेलापुर से शॉर्ट

ओरिजिनेशन होगी

ट्रांस-हार्बर लाइन

दिनांक 22.11.2025 को निम्न डाउन लोकल सेवाएं रह (कैंसिल) रहेंगी ठाणे से 22.55 बजे निकलने वाली पनवेल की डाउन लोकल

दिनांक 23.11.2025 को निम्न डाउन लोकल सेवाएं रह (कैंसिल) रहेंगी ठाणे से 08.41 बजे और 10.01 बजे निकलने वाली पनवेल की डाउन लोकल। ठाणे से 09.04 बजे और 11.42 बजे निकलने वाली नेरुल की डाउन लोकल।

वाशी के लिए ठाणे से 10.20 बजे निकलने वाली डाउन लोकल दिनांक 23.11.2025 को निम्न अप लोकल सेवाएं रह (कैंसिल) रहेंगी

वाशी से 10.58 बजे निकलने वाली अप लोकल,। नेरुल से 09.42 बजे निकलने वाली अप लोकल। पनवेल से 07.43 बजे, 08.04 बजे, 09.01 बजे, 10.41 बजे और 11.02 बजे निकलने वाली अप लोकल। निम्नलिखित उपनगरीय ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन।पनवेल के लिए ठाणे से दिनांक 22.11.2025 को 23.32 बजे और दिनांक 23.11.2025 को 00.05 बजे निकलने वाली डाउन लोकल बेलापुर में शॉर्ट टर्मिनेट होंगी।

दिनांक 23.11.2025 को 12.00 बजे ठाणे से निकलने वाली डाउन लोकल

नेरुल से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

आखिरी (लास्ट) लोकल - डाउन

ब्लॉक से पहले डाउन हार्बर लाइन पर पनवेल के लिए आखिरी लोकल सीएसएमटी से दिनांक 23.11.2025 को 00.40 बजे निकलेगी।

ब्लॉक से पहले डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन पर पनवेल के लिए आखिरी ट्रेन ठाणे-पनवेल लोकल होगी जो ठाणे से 22.11.2025 को 23.14 बजे निकलेगी।

ब्लॉक से पहले 38 ट्रांस-हार्बर लाइन पर बेलापुर के लिए आखिरी लोकल ठाणे-बेलापुर लोकल होगी जो ठाणे से दिनांक 23.11.2025 को 00.05 बजे निकलेगी।

आखिरी (लास्ट) लोकल - अप ब्लॉक से पहले अप हार्बर लाइन पर सीएसएमटी के लिए आखिरी ट्रेन पनवेल- सीएसएमटी लोकल होगी, जो गलोलक 23.11.2025 को 04.49 बजे पनवेल से निकलेगी।

आखिरी (लास्ट) लोकल - अप ब्लॉक से पहले अप हार्बर लाइन पर सीएसएमटी के लिए आखिरी ट्रेन पनवेल- सीएसएमटी लोकल होगी, जो गलोलक 23.11.2025 को 04.49 बजे पनवेल से निकलेगी।

पहली लोकल - डाउन ब्लॉक के बाद डाउन हार्बर लाइन पर

ब्लॉक से पहले अप ट्रांस-हार्बर लाइन पर ठाणे के लिए आखिरी लोकल पनवेल- ठाणे लोकल होगी, जो दिनांक 23.11.2025 को 12.19 बजे पनवेल से निकलेगी।

ये ब्लॉक बुनियादी ढांचे के रखरखाव और संरक्षा के लिए आवश्यक हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इससे होने वाली असुविध के लिए रेलवे प्रशासन को सहयोग करें।

यदि आवश्यक हो तो ट्रांस-हार्बर लाइन पर ठाणे के लिए आखिरी लोकल पनवेल- ठाणे लोकल होगी, जो दिनांक 23.11.2025 को 12.19 बजे पनवेल से निकलेगी।

यदि आवश्यक हो तो ट्रांस-हार्बर लाइन पर ठाणे के लिए आखिरी लोकल पनवेल- ठाणे लोकल होगी, जो दिनांक 23.11.2025 को 12.19 बजे पनवेल से निकलेगी।

-पनवेल लोकल होगी, जो दिनांक 23.11.2025 को 10.52 बजे सीएसएमटी से निकलेगी। ब्लॉक के बाद डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन पर पनवेल के लिए पहली ट्रेन ठाणे-पनवेल लोकल होगी, जो दिनांक 23.11.2025 को 12.49 बजे ठाणे से निकलेगी। ब्लॉक के बाद डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन पर नेरुल के लिए पहली ट्रेन दिनांक 23.11.2025 को 12.29 बजे नेरुल से निकलेगी।

पहली लोकल - अप ब्लॉक के बाद अप हार्बर लाइन पर वडाला रोड के लिए पहली लोकल पनवेल-वडाला रोड लोकल होगी जो दिनांक 23.11.2025 को 12.03 बजे पनवेल से निकलेगी।

ब्लॉक के बाद अप हार्बर लाइन पर सीएसएमटी के लिए पहली ट्रेन पनवेल- सीएसएमटी लोकल होगी जो दिनांक 23.11.2025 को 12.07 बजे पनवेल से निकलेगी।

ब्लॉक के बाद अप ट्रांस-हार्बर लाइन पर ठाणे के लिए पहली लोकल पनवेल- ठाणे लोकल होगी जो दिनांक 23.11.2025 को 12.19 बजे पनवेल से निकलेगी।

यदि आवश्यक हो तो ट्रांस-हार्बर लाइन पर ठाणे के लिए आखिरी लोकल पनवेल- ठाणे लोकल होगी, जो दिनांक 23.11.2025 को 12.19 बजे पनवेल से निकलेगी।

यदि आवश्यक हो तो ट्रांस-हार्बर लाइन पर ठाणे के लिए आखिरी लोकल पनवेल- ठाणे लोकल होगी, जो दिनांक 23.11.2025 को 12.19 बजे पनवेल से निकलेगी।

यदि आवश्यक हो तो ट्रांस-हार्बर लाइन पर ठाणे के लिए आखिरी लोकल पनवेल- ठाणे लोकल होगी, जो दिनांक 23.11.2025 को 12.19 बजे पनवेल से निकलेगी।

टोरेंट पावर और एमएसईडीसीएल का विशेष ग्राहक सेवा शिविर

SMK और भिवंडी में 25-26 नवंबर को मिलेगा उपभोक्ताओं को समाधान

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। टोरेंट पावर लिमिटेड, जो भिवंडी तथा शिल-मुम्ब्रा-कलवा (SMK) क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के फ्रंचाइजी के रूप में कार्यरत है, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दो दिवसीय विशेष ग्राहक सेवा शिविर आयोजित करने जा रहा है। कंपनी का कहना है कि उसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को आसान, त्वरित और प्रभावी सेवा उपलब्ध कराना है।

शिविर का आयोजन 25 और 26 नवंबर 2025 को किया जाएगा।

25 नवंबर को शिविर शिल-मुम्ब्रा-कलवा (SMK) क्षेत्र में टोरेंट कस्टमर केयर सेंटर, अरिहंत आरोही बिल्डिंग, कल्याण-शिल रोड पर लगेगा।

वहीं 26 नवंबर को शिविर भिवंडी में टोरेंट कस्टमर केयर सेंटर, अर्श रजिडेंसी, चाविंद्रा रोड, आमपाड़ा में आयोजित होगा।

दोनों शिविरों का समय सुबह 10:30

बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा।

टोरेंट पावर के जनसंपर्क अधिकारी चेतन विदयानी ने बताया कि शिविर में कंपनी के अधिकारी एवं एमएसईडीसीएल के अधिकारी संयुक्त रूप से उपस्थित रहेंगे, जिससे उपभोक्ता अपनी किसी भी लंबित शिकायत, बिलिंग समस्या, कनेक्शन, वोल्टेज, मीटरिंग सहित अन्य मुद्दों का समाधान एक ही स्थान पर कर सकेंगे।



साथ ही एमएसईडीसीएल से जुड़े मामलों की भी सुनवाई और निपटारा शिविर में ही किया जाएगा। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस विशेष सेवा शिविर का लाभ उठाएँ और अपनी लंबित समस्याओं का समाधान समय पर कराएँ। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता टोरेंट पावर हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

सोसाइटी परिसर में तीन कुत्तों की मौत से हड़कप?

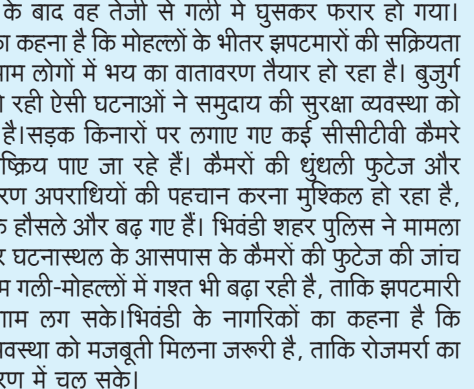
सोसायटी के दो चेयरमैन पर जहर देने का मामला दर्ज
भिवंडी। भिवंडी के शांतिनगर क्षेत्र में तीन आवारा कुत्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और एक के गंभीर हालत में मिलने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर सोसायटी के दो चेयरमैन के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना 20 नवंबर की रात ऑरेंटेड राइस कॉलैस्टो सोसायटी, साईबाबा मंदिर के पास हुई। शिकायतकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता अनुपमा जयतिलाल जैन (30) ने शांतिनगर पुलिस को बताया कि सोसायटी परिसर में रहने वाले तीन आवारा कुत्ते-ब्राऊनी, सिंगार और चिक्कु-मूत पाए गए, जबकि एक अन्य कुत्ता जुजु गंभीर अवस्था में मिला। अनुपमा जैन ने अपनी शिकायत में सोसायटी के दो चेयरमैन-सवित्राबेन अनुमाडुल और रमेश पर आरोप लगाया है कि दोनों कुत्तों को लेकर अकसर आपत्ति जताते थे और उन्हें किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कराकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। शांतिनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(C) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस उपनिरीक्षक गोरे इस मामले की जांच कर रहे हैं। मृत कुत्तों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि घायल कुत्ते का इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

तलाक का दबाव बनाकर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी पति समेत चार पर मामला दर्ज

भिवंडी। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक 30 वर्षीय महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उपीड़न, धमकी और अश्लील वीडियो वायरल करने जैसी गंभीर हरकतों के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि पति तलाक के लिए दबाव बना रहा था और बात न मानने पर उसके निजी फोटो और वीडियो प्रसारित करने की धमकी देता था। शिकायत के अनुसार , पीड़िता भिवंडी की रहने वाली है। उसने बताया कि पति कलाम हुसैन मोहम्मद सैय्यद, उसकी सास, ससुर और ननद उसे मायके से सोने-चांदी के जेवर और नकदी लाने के लिए मजबूर करते थे। विरोध करने पर उसके साथ मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना की जाती थी। पीड़िता ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के मउआईम प्रयागराज जिले के रजवापुर गांव में रहने के दौरान पति ने बेडरूम में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। पीड़िता का कहना है कि पति इन निजी वीडियो और फोटो को दिखाकर तलाक के लिए दबाव डालता था। तीन अक्टूबर 2025 को आरोपी पति ने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी अपलोड कर दिए, यही नहीं उसने वीडियो एक रिश्तेदार के मोबाइल पर भेज दिया। जिससे वह बुरी तरह दहशत में आ गई। शांतिनगर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति कलाम हुसैन मोहम्मद सैय्यद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67ए के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार जांच जारी है और आरोपी पति की तलाश की जा रही है।

भिवंडी में झपटमारों का आतंक गल्ली-मोहल्लों में बुजुर्ग महिलाएं असुरक्षित

भिवंडी। भिवंडी शहर में झपटमारों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसका सीधा असर गल्ली-मोहल्लों की बुजुर्ग महिलाओं की सुरक्षा पर दिखाई दे रहा है। पन्नानगर क्षेत्र में हुई ताज़ा वारदात से स्थानीय नागरिकों में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस के मुताबिक पन्नानगर में रहने वाली 60 वर्षीय आगंब्या सत्तया मिट्टयपेल्ली सुबह लगभग 11 बजे अपने घर की ओर लौट रही थीं। इसी दौरान एक अज्ञात युवक पास की गली से निकलकर आया और उनकी गर्दन से 30 ग्राम वजनी सोने की चैन झपटकर भाग निकला। चैन की कीमत लगभग 90 हजार रुपये आंकी गई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी युवक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच थी। वह रंगीन फूलों की शर्ट और काली पैंट पहनने हुए था। चैन छीनने के बाद वह तेजी से गली में घुसकर फरार हो गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मोहल्लों के भीतर झपटमारों की सक्रियता बढ़ गई है, जिससे आम लोगों में भय का वातावरण तैयार हो रहा है। बुजुर्ग महिलाओं के साथ हो रही ऐसी घटनाओं ने समुदाय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है।सड़क किनारों पर लगाए गए कई सीसीटीवी कैमरे तकनीकी रूप से निष्क्रिय पाए जा रहे हैं। कैमरों की धुंधली फुटेज और खराब स्थिति के कारण अपराधियों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है, जिससे अपराधियों के हौंसले और बढ़ गए हैं। भिवंडी शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटनास्थल के आसपास के कैमरों की फुटेज की जांच में जुटी है। पुलिस टीम गली-मोहल्लों में गश्त भी बढ़ा रही है, ताकि झपटमारी की वारदातों पर लगाम लग सके।भिवंडी के नागरिकों का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलना जरूरी है, ताकि रोजमर्रा का जीवन निर्भय वातावरण में चल सके।



चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समयपूर्व रिहाई और अंतरिम जमानत को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि सजायापत्ता कैदी की समयपूर्व रिहाई पर फैसला लेना सिर्फ सरकार का अधिकार है और इसे कोर्ट में अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। अदालत ने कहा कि सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी कोर्ट की कस्टडी में नहीं रहता, इसलिए कोर्ट से जमानत या अंतरिम जमानत की मांग करना न्यायिक प्रक्रिया के अनुसूच नहीं है।

न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार और न्यायमूर्ति एम ज्योति रामन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी 19 नवंबर को जुबैथा बैगम और अन्य 12 याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज कर करते हुए की। इन

याचिकाओं में कैदियों को अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी, जबकि उनकी समयपूर्व रिहाई की अर्जी अभी सरकार के पास लंबित



थी। कोर्ट ने साफ कहा कि चूंकि सजा सुनाए जाने के बाद कैदी जेल विभाग की कस्टडी में होता है, इसलिए कोर्ट उसके लिए अंतरिम जमानत के आदेश जारी नहीं कर सकता।

सजा के बाद कोर्ट की कस्टडी खत्म- हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि जब आरोपी को सजा सुना दी जाती है, तो कोर्ट की कस्टडी खत्म हो जाती है और वह सरकार या जेल प्राधिकरण के अधीन हो जाता है। इसलिए समयपूर्व रिहाई का मुद्दा भी सरकार के पास ही विचार के लिए जाता है। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत

हाईकोर्ट अंतरिम जमानत नहीं दे सकता, क्योंकि इस स्थिति में कोर्ट के पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं होता। कैदियों को केवल तमिलनाडु संस्थान ऑफ सेंटेंस रूल्स के तहत ‘सजा निबंधन’ का विकल्प मिलता है।

याचिकाकर्ताओं की मांग पर सख्त टिप्पणी

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर सभी याचिकाएं इस आधार पर टिक नहीं सकती कि सरकार में लंबित प्रकरण के चलते कैदियों को अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कई कारकों को ध्यान में रखते हुए समयपूर्व रिहाई पर फैसला करना होता है। इसलिए इसे अधिकार मानकर कोर्ट में मांग करना गलत है। अदालत ने साफ किया कि अंतरिम जमानत, जब सजा पूरी सुनाई जा चुकी हो, कोर्ट द्वारा नहीं दी जा सकती।

जरूरतमंद मामलों में सरकार खुद फैसला करे- हाईकोर्ट

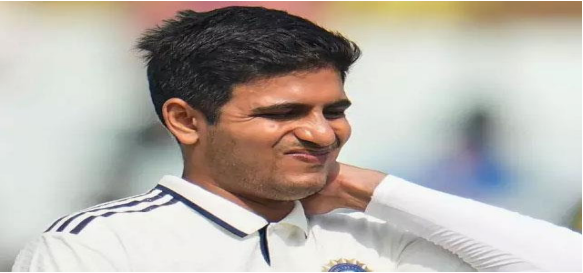
खंडपीठ ने यसु मामले का हवाला देते हुए कहा कि संस्थान ऑफ सेंटेंस रूल्स के नियम 40 के तहत सरकार के पास यह विवेकाधिकार है कि वह किसी भी

दूसरे टेस्ट से गिल की गैरमौजूदगी पर बोले रोड्स, भारत के पास कई विकल्प

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉटी रोड्स का मानना है कि भारत को शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल की कमी खलेगी लेकिन मेजबान टीम के पास नियमित कप्तान की कमी पूरी करने के लिए कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं।

गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार से गुवाहाटी में शुरू हो रहे दूसरे मैच से पहले शुक्रवार को टीम से रिलीज कर दिया गया था। वह कोलकाता में पहले टेस्ट की हार का पी में बल्लेबाजी करते हुए गर्दन में ऐंठन से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे। रोड्स ने शुक्रवार को यहां 'फिक्की टर्फ 2025' 15वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन के मौके पर कहा, 'कभी-कभी भारत की ताकत भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी करती है। उनके पास कई बेहतरीन

क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ऐसे में टीम में किसे शामिल किया जाए और किसे बाहर रखा जाए, यह तय करना बहुत मुश्किल होता है।' उन्होंने कहा, 'यह एक बड़ी समस्या है और यह साफ दिखाई देता है। जब भी किसी एक खिलाड़ी की जगह लेने की बात आती है तो भारत के पास ढेरों विकल्प होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस खिलाड़ी को मौका मिलता है।' इस 56 साल के पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि गिल की जगह



जिसे भी मौका मिले उसे अपनी काबिलियत तुरंत साबित करनी होगी क्योंकि भारतीय टीम में जगह के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है। उन्होंने कहा, 'टीम में आने वाले खिलाड़ी के सामने बड़ा सवाल यही होगा कि क्या वे इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि भारत की इस मजबूत प्रणाली के साथ बड़ा मुद्दा यही है कि आपको शायद एक ही मौका मिले।'

अपने समय के सर्वश्रेष्ठ

क्षेत्ररक्षक रहे रोड्स ने कहा, 'आप अगले टेस्ट में गिल को बाहर नहीं बिठा सकते तो ऐसे में उनकी जगह लेने वाले खिलाड़ी को सिर्फ एक टेस्ट में खेलने का मौका मिलेगा और यह मानसिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में वे जिस खिलाड़ी का भी चयन करेंगे, उसके कौशल में कोई कमी नहीं होगी।' उन्होंने कहा, 'भारत के लिए ऐसे में एकादश का चयन करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। रोड्स ने हाल ही में पहली बार वनडे विश्व कप जीतने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी बधाई दी। उन्होंने कहा, 'उम्मीद है, वे (भारतीय प्रशंसक) महिलाओं के मैचों में भी दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देंगे। भारत में महिला क्रिकेट आसमान छूने वाला है। मैं महिला टीम के लिए भी ऐसा ही समर्थन देखना चाहता हूं।'

तेल विपणन कंपनियों का परिचालन लाभ चालू वित्त वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ने का अनुमान-रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) तेजी से वापसी के लिए तैयार हैं और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में उनका परिचालन लाभ 50 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 18 से 20 डॉलर प्रति बैरल होने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने शुक्रवार को कहा कि स्थिर खुरदरा ईंधन कीमतों और कच्चे तेल की अनुकूल गतिशीलता के बीच मजबूत विपणन मार्जिन से यह लाभ बढ़ेगा। तेल विपणन कंपनियां रिफाइनिंग (सकल रिफाइनिंग मार्जिन या जीआरएम) और पेट्रोल, डीजल व अन्य ईंधनों के विपणन से आय अर्जित करती हैं।

क्रिसिल रेटिंग्स ने बयान में

कहा, "चालू वित्त वर्ष में विपणन मार्जिन में सुधार, जीवाश्म ईंधन की वैश्विक मांग में धीमी वृद्धि के कारण रिफाइनिंग मार्जिन में आई कमी की भरपाई से कहीं अधिक होगा क्योंकि दुनिया स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही है।" बेहतर लाभ से नकदी संचय बढ़कर 75, 000-80, 000 करोड़ रुपए हो जाएगा जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह करीब 55, 000 करोड़ रुपए था। मजबूत नकदी प्रवाह इस क्षेत्र के नियोजित 90, 000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय को सहारा देगा जो मुख्यतः पुरानी परियोजनाओं के विस्तार और घरेलू मांग-संचालित परियोजनाओं पर

केंद्रित है। कच्चे तेल की कीमतें घटकर 65-67 डॉलर प्रति बैरल रहने की उम्मीद है जिससे सकल राजस्व (जीआरएम) चार से छह डॉलर प्रति बैरल पर सीमित रहेगा। इसके विपरीत विपणन मुनाफा बढ़कर करीब 14 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल (लाभगम आठ रुपए प्रति लीटर) हो जाने का अनुमान है जिससे समग्र परिचालन मार्जिन में वृद्धि होगी। पिछले पांच वित्त वर्ष में भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने तेल की कीमतों को प्रभावित किया है जबकि खुरदरा ईंधन की कीमतें सीमित दायरे में रही हैं। क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, "चालू वित्त वर्ष में कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर होने के बावजूद 65-67 डॉलर प्रति बैरल तक नरम पड़ने की संभावना है। वैश्विक मांग में नरमी और ऊर्जा बदलाव के रक्षान से 'रिफाइनिंग स्प्रेड' पर दबाव के कारण जीआरएम के चार से छह डॉलर प्रति बैरल पर बने रहने की संभावना है।

भारतीय स्टार स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से की सगाई, पीएम मोदी ने शादी की तारीख का किया खुलासा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की चमकती सितारा और वर्ल्ड कप विजेता ओपनर स्मृति मंधाना ने अंततः अपने प्रशंसकों के बीच लंबे समय से चल रही अफवाहों पर विराम लगाया है। शादी की गैर सगाई की आधिकारिक घोषणा कर दी है। एक खूबसूरती से कोरियोग्राफ किए गए इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए की गई इस घोषणा ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। इस रील में उनकी टीममेट्स भी उनके साथ नज़र आईं। वीडियो में भले ही शादी की तारीख नहीं बताई गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपल को शुभकामनाएं देते हुए बड़ी जानकारी साझा कर दी जिसमें शादी की आधिकारिक तारीख शामिल है।

स्मृति मंधाना ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक आकर्षक और मनोरंजक रील पोस्ट की, जिसने कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज बटोर लिए। इस वीडियो में उनके साथ जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी नज़र

आईं, जिनके साथ उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के गाने 'समझो हो ही गया' पर एक सिंक्रनाइज़ कोरियोग्राफ रूटीन प्रस्तुत किया। वीडियो की अंतिम झलक में मंधाना

कैमरे की ओर हाथ बढ़ाती हैं, जहाँ उनकी सगाई की अंगूठी साफ दिखाई देती है। इस एक फ्रेम ने फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी और लंबे समय से चल रही



खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 में 8 प्रतिशत बढ़कर 35.77 करोड़ टन पर : सरकारी आंकड़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में खाद्यान्न उत्पादन फसल वर्ष 2024-25 में आठ प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 35.77 करोड़ टन हो गया। बुधस्तिवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) में खाद्यान्न उत्पादन 33.23 करोड़ टन रहा था। फसल वर्ष 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किसानों के प्रयासों और उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और खरीद सहित सरकारी नीतियों का नतीजा है।

अंतिम अनुमान के अनुसार, 2024-25 में गेहूँ का उत्पादन रिकॉर्ड 11.79 करोड़ टन रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 11.33 करोड़ टन था। चावल का उत्पादन 2024-25 में बढ़कर रिकॉर्ड 15.02 करोड़ टन हो गया। एक साल पहले 2023-24 में यह 13.78 करोड़ टन था। मोटे अनाज का उत्पादन भी 5.69 करोड़ टन से बढ़कर 6.39 करोड़ टन हो गया। दालों का उत्पादन बढ़कर 2.57 करोड़

टन हो गया जो 2023-24 में 2.42 करोड़ टन था। गैर-खाद्यान्न श्रेणी में, तिलहनों का उत्पादन 3.97 करोड़ टन से बढ़कर 4.30 करोड़ टन हो गया।

नकदी फसलों में, गन्ने का उत्पादन 45.46 करोड़ टन रहा जो एक साल पहले 2023-24 में 45.31 करोड़ टन था। हालांकि, कपास का उत्पादन फसल वर्ष 2024-25 में घटकर 2.97 करोड़ गांठ (एक गांठ बराबर 170 किलोग्राम) रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 3.25 करोड़ गांठ था। चौहान ने कहा कि पिछले दस वर्षों में देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 2024-25 में 35.77 करोड़ टन हो गया जो 2015-16 में 25.15 करोड़ टन था।



उदयपुर में नेत्रा मंटेना की शादी! जस्टिन बीबर, जेनिफर लोपेज और बॉलीवुड सितारे बिखेरेंगे जलवा, भव्यता चरम पर होगी

उदयपुर में इस साल का सबसे गैंड वेंडिंग सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मैनेजट रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना, एंटरप्रेन्योर वामसी गदिराजू के साथ शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रही हैं। 21-23 नवंबर तक चलने वाले तीन दिन के फंक्शन ने शहर के झील किनारे बने महलों को ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब में बदल दिया है, जिसमें इंटरनेशनल सुपरस्टार और बॉलीवुड रॉयल्टी राजस्थान आ रहे हैं।

हाँ! आपने सही पढ़ा, जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज जैसे इंटरनेशनल पॉप सिंगर से लेकर कृति सनोन और रणवीर सिंह जैसे बॉलीवुड सेलेब्स शादी में स्ट्रेज पर आग लगाते हुए दिखाई देंगे।

इंटरनेशनल आइकॉन जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज के म्यूजिकल इवनिंग में हेडलाइन करने की उम्मीद है, साथ ही टिफ़ो, ब्लैक कॉफी, सर्क डू सोलैल जैसे दुनिया भर के जाने-

माने परफॉर्मर और डीजे अमन नागपाल भी शामिल होंगे। उनकी मौजूदगी ने ऑनलाइन सबका ध्यान खींचा है, जिससे यह प्राइवेट इवेंट कलचरल बातचीत का मुद्दा बन गया है।



बॉलीवुड के बड़े नाम भी गेस्ट लिस्ट का हिस्सा हैं, जिसमें रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, करण जौहर, कृति सनोन और दूसरे लोगों के आने की उम्मीद है। शादी असल में एक स्टार-स्टडेड पेरडे में बदल गई है, जिसमें ए-लिस्टर्स के प्लो को मैनेज करने के लिए हाई सिक्वोरिटी

और टाइट शेड्यूल हैं।

शादी के बड़े फंक्शन उदयपुर के द लीड पैलेस, ज्ञाना महल और पिछोला झील पर बने आइलैंड पैलेस में हो रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक, वेंडिंग प्लानर्स ने अपने काम के लिए जानी जाती की कलचरल रिचनेस को हाईलाइट करने के लिए हेरिटेज को रोलबल ग्लैमर के साथ मिलाने के लिए जाने-माने डेकोर डिजाइनर्स, शेपस और ट्रेंडिशनल फोक ग्रुप्स को एक साथ लाया है।

नेत्रा मंटेना, जो अपने परिवार के बिजनेस एम्पायर के तहत फ़िर्ज़ेप्री और केनेस इनिशिएटिव में अपने काम के लिए जानी जाती हैं, ज़्यादातर लाइलाइट से दूर रही हैं। दूल्हा, वामसी गदिराजू, एक एंटरप्रेन्योर और टेक प्रोफेशनल हैं।

एशेज देखकर हुई जलन, द. अफ्रीकी कप्तान बावुमा ने कहा- हम भारत के खिलाफ बड़ी सीरीज डिजर्व करते हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही दो-टेस्ट की छोटी सीरीज ने प्रोटियाज कप्तान टेम्बा बावुमा की नाराजगी को खुलकर उजागर कर दिया है।`ऊप चैंपियन बनने के बावजूद साउथ अफ्रीका को भारत जैसे दिग्गज के खिलाफ सिर्फ दो टेस्ट खेलने पड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों एशेज में पाँच मैचों की लंबी भिड़ंत का आनंद ले रही हैं। बावुमा का मानना है कि दो सबसे मजबूत रेड-बॉल टीमों के बीच इतनी छोटी सीरीज न तो खिलाड़ियों के साथ न्याय है, न फैंस के साथ। यह मुद्दा फिर से क्रिकेट शेड्यूलिंग और कर्मशियल प्राथमिकताओं पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत के दौरान बावुमा ने बताया कि उन्होंने सुबह ऑस्ट्रेलिया में चल रहा एशेज टेस्ट देखा और इस दौरान 'थोड़ी

जलन' महसूस की। उन्होंने कहा, 'आज सुबह उठकर एशेज देखा। पाँच टेस्ट खेलते देख थोड़ा जलन हुई। वे एक-दूसरे पर हावी होंगे, और हमें सिर्फ दो मैच मिले हैं।' यह बयान साफ दिखाता है कि कप्तान इस छोटी सीरीज से खुश नहीं हैं, खासकर तब जब उनकी टीम मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है। बावुमा ने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में साउथ अफ्रीका को भारत के खिलाफ चार या 5 टेस्ट की सीरीज मिलेगी। उन्होंने कहा, 'उम्मीद है कि जल्द ही हम इंडिया के खिलाफ चार टेस्ट खेलने



के लिए लौटेंगे।' बावुमा के अनुसार, मजबूत टीमों के बीच लंबी सीरीज ही फैंस को असली रोमांच देती है और खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका भी।

प्रोटियाज कप्तान ने स्पष्ट किया कि टेस्ट सीरीज के मैचों की संख्या खिलाड़ी तय नहीं करते। यह पूरा मामला बोर्ड्स की कर्मशियल प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। एशेज, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (भारत-ऑस्ट्रेलिया), एंडरसन-लेडवुल ट्रॉफी (भारत-इंग्लैंड) इन सीरीज को 5 टेस्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से सबसे 'लाभकारी' मानी जाती



61 आईपीओ ने जुटाए 90, 000 करोड़ लेकिन रिटर्न ने किया निराश

नई दिल्ली (एजेंसी)। अगर आप आने वाले समय में आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो हाल के आंकड़े आपको ज्यादा सतर्क कर सकते हैं। पिछले 90 दिनों में कुल 61 आईपीओ लॉन्च हुए, जिनके माध्यम से कंपनियों ने 90, 000 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी रकम जुटाई है। हालांकि कंपनियों ने पूंजी जुटाने में सफलता हासिल की लेकिन निवेशकों को मिलने वाला रिटर्न काफी मिला-जुला रहा।

ट्रेंडलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, 61 में से 44 आईपीओ ने लिस्टिंग के समय 10% से कम रिटर्न दिया, जबकि 19 आईपीओ ने या तो कोई फायदा नहीं पहुंचाया या सीधे नुकसान कराया। यह स्थिति 2021-22 के मुकाबले बिल्कुल अलग है, जब नए आईपीओ लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों के लिए भारी मुनाफा लेकर आते थे। इसके अलावा अब लगभग आधे आईपीओ

अपने इश्यू प्राइस से नीचे कारोबार कर रहे हैं जबकि इन पर निवेशकों खासकर रिटेल निवेशकों का भारी समर्थन देखने को मिला था।

अगस्त से नवंबर के बीच कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 1.03 लाख करोड़ रुपए जुटाए। इस अवधि में टाटा कैंपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, लैसकार्ट, ग्रे और टेनेको क्लीन एयर जैसी बड़ी कंपनियों के साथ-साथ टेक प्लेटफॉर्म, वित्तीय सेवाओं, इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, केमिकल और कंप्यूटर ब्रांड्स के आईपीओ शामिल रहे। लिस्टिंग के बाद इन कंपनियों का प्रदर्शन एक



जैसा नहीं रहा। इश्यू प्राइस से अब तक का औसत रिटर्न लगभग 11% रहा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम है। 61 में से 26 कंपनियां अपने इश्यू प्राइस से नीचे हैं, जबकि 35 आईपीओ अभी भी लाभ में बने हुए हैं।

सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि जिन आईपीओ में रिटेल निवेशकों ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी, वे ही सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वालों में शामिल हो गए। उदाहरण के तौर पर, डेव एक्सेलेरेटर को रिटेल द्वारा 164 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया गया था लेकिन यह अब अपने इश्यू प्राइस से करीब 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसी तरह हीएमएस टीएमटी, जिसे 47 गुना बोली मिली थी, 37% टूट चुका है। सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और रेगल रिसोर्सेज भी भारी सब्सक्रिप्शन के बावजूद गिरावट में हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आईपीओ भी, बड़ी बोली के बाद, निवेशकों को नुकसान ही दे रहे हैं।

मध्य रेल
सोलापुर मंडल
विद्युत कार्य
 निविदा क्र. - सोला/क.वि./नि/2025/26. भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि.), मध्यरेल, सोलापुर, निम्नलिखित कार्य के लिए ख्याती प्राप्त, अनुभवी और लाईसेंसधारी विद्युत ठेकेदारों से रेल्वे की ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट www.ireps.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित करते है। कार्य का नाम: टिकेकरवाडी में प्रस्तावित कोचिंग रखरखाव डिपो (चरण-1) के संबंध में विद्युत टीआरडी का कार्य। कार्य की लागत: ₹ 5,62,96,465.20. बयाना राशि: ₹ 4,31,500/- कार्य पूरा करने की अवधि: 12 माह. निविदा प्रस्ताव की वैधता: 60 दिन। वेबसाइट पर निविदा बंद होने की तिथि और समय: दि. 15.12.2025 को 15:00 बजे।
 वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि.) Akar/Sur-77 मध्य रेल, सोलापुर
टिकट के लिए UTS APP डाउनलोड करें
मध्य रेल
सोलापुर मंडल
ई-निविदा सूचना
मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) सोलापुर, भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिये ई निविदाएं आमंत्रित करते है। 1. ई-निविदा सूचना क्र. 44-2025-SrDENC. कार्य का नाम : 1-Construction of New quarters at KEM (type-II 04 units), JEUR (Type-II 04 units) BLNI (Type-II 04 units) & WSB (Type-II 04 unit) under ADEN/BG/KWV. 2- Construction of New quarters at SGRE (type-II 04 units),JTRD (type-II 04 units), ARAG (type-II 4 units), YSI (Type-II 02 units) & DKY (Type-II 02 units) under ADEN/PVR & ADEN/LUR. 3- Construction of quarters in lieu of old quarters at SUR (Type-III 04 units & Type-IV 02 units) under ADEN/W/W/SUR sub division, PJR(Type-II 04 units) & YSI (Typell 02 units) under ADEN/LUR sub division. अनुमानित लागत: ₹ 9,02,55,439.70. बयाना रकम: ₹ 6,01,300/- समापन की अवधि: 12 महिने. अनुरक्षण की अवधि: 2 4 महिने. www.ireps.gov.in इस वेबसाइट पर टेंडर अपलोड करने की अंतिम दिनांक और समय: 1 2 . 1 2 . 2 0 2 5 को 15:00 बजे तक, www.ireps.gov.in इस वेबसाइट पर टेंडर खुलने का दिनांक और समय: 12.12.2025 को 15:30 बजे. निविदाकारों से निवेदन है की कोई बदलाव/शुद्धिपत्र (यदि हो) के लिये Website: www.ireps.gov.in पर टेंडर बंद होने की तारीख तक समय समय पर भेंट दे।
 मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) मं.रे. सोलापुर टिकट के लिए UTS APP डाउनलोड करें

मध्य रेल
भुसावल मंडल
खुली ई-निविदा
 निविदा सूचना सं. भुसावल इलेक्ट टीआरडी_74_2025, दिनांक 19/11/2025. भारत के महामाहिम राष्ट्रपति हेतु सीनियर डिबीजनल बिजली इंजीनियर (क.वि.) मध्य रेल, भुसावल द्वारा निम्न लिखित कार्य हेतु डीजीटेली हस्तक्षरित ऑनलाइन ओपन ई निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य का नाम: निम्नलिखित कार्यो के संबंध में, 25 केवी, सिंगल फेज, ए.सी. ओएचई कार्यो का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग : a. देवलाली स्टेशन के BSL एंड पर UP दिशा में 2 स्टेबलिंग लाइन 750M (UP और DN लूप) का प्रोविज़न । b. देवलाली स्टेशन फेज-II में C&W जांच और स्टेबलिंग सुविधाओं का प्रोविजन। c. नासिक स्टेशन की 2 स्टेबलिंग लाइन का प्रोविजन। d. नासिक रोड स्टेशन पर PF नंबर 2/3 CSMT एंड पर COP के एक्सटेंशन का प्रोविजन। e. नासिक रोड स्टेशन पर PF नंबर 4 पर कवर ओवर प्लेटफॉर्म (COP) का प्रोविजन। f. असवाली-नासिक सेक्शन में ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग (ABS) के कनेक्शन में AT सप्लाई का प्रोविजन। g. इगतपुरी-असवाली सेक्शन (26.00 KM) में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग (ABS) देकर मोबिलिटी इम्यूवमेंट और कैपेसिटी बढ़ाने के कनेक्शन में AT सप्लाई का प्रोविजन।। कार्य की लागत: ₹ 7,71,56,720.50. बयाना राशी: ₹ 5,35,800/- निविदा जमा करने की अंतिम तारीख, समय: 12.12.2025 up to 15.00 hrs. अतिरिक्त जानकारी के लिए वेब साइट का पता: www.ireps.gov.in Akar/BSL-11
टिकट के लिए UTS APP डाउनलोड करें

मध्य रेल
ई-निविदा सूचना संख्या:
CR-NGP-M-11-DT-18-11-2025
 कार्य का नाम: "नागपुर मंडल स्थित एलएचबी कोचों में आरडीएसओ, एमसीएफ-आरबीएल द्वारा निर्धारित प्रेशराइज्ड प्लशिंग सिस्टम में संशोधन का कार्य"; कार्य का स्थान: कोचिंग डिपो नागपुर डिबीजन/मध्य रेलवे. कार्य कि अवधि: एक साल. कार्य का अनुमानित मूल्य: ₹ 13,46,616/- (तेरह लाख, छियालीस हजार, छह सौ सोलह रूपये मात्र). निविदा की सुरक्षा: ₹ 26,900/- (छब्बीस हजार नौ सौ रूपये मात्र). निविदा दस्तावेज का मूल्य: कुछ नहीं. निविदा बंद होने की अंतिम तारीख तथा समय: 09.12.2025 को 12.30 बजे. विस्तृत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in पर लॉग ऑन करें.
 वरि. मंडल यांत्रिक इंजिनियर, मध्य रेलवे, नागपुर टिकट के लिए UTS APP डाउनलोड करें

स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में 20 दिवसीय पी.जी. ट्रांजिशनल करिकुलम का उद्घाटन



प्रयागराज। स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, प्रयागराज के अहमद उस्मानी ऑडिटोरियम में इस वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट विभाग में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 20 दिवसीय ट्रांजिशनल करिकुलम का उद्घाटन समारोह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. वसीम अहमद की अध्यक्षता में धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीनस्थ आयुष विभाग की महानिदेशक मानननीया श्रीमती चैत्रा वी (आई.ए.एस.), विशेष अतिथि प्रोफेसर जी.एस. तोमर तथा यस्मनील उस्मानी उपस्थित रहे।

एन.सी.आई.एस.एम., नई दिल्ली के सुनहरे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए

इस 20 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को यूनानी तिब की महत्ता और उपयोगिता तथा आधुनिक आवश्यकताओं से अवगत कराना, उनमें शोध एवं बौद्धिक आत्मविश्वास जगाना, आयुष विभाग के नियम-कानूनों की पूर्ण जानकारी देना तथा बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन करना है। कार्यक्रम का शानदार आगाज़ तिलावत-ए-कलाम-ए-पाक से हुआ। विभागाध्यक्ष माहियतुल अमराज़ प्रोफेसर इरफान अहमद ने अतिथियों का विशेष स्वागत करते हुए स्वागत संबोधन पेश किया। एकेडमिक इंचार्ज प्रोफेसर नजीब हंज़ला अम्मरा ने बेहतरीन एवं व्यापक अंदाज़ में कॉलेज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास

यात्रा पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि, आयुष विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की महानिदेशिका माननीया श्रीमती चैत्रा वी ने अपने शोध एवं बौद्धिक आत्मविश्वास जगाना, आयुष विभाग के नियम-कानूनों की पूर्ण जानकारी देना तथा बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन करना है। कार्यक्रम का शानदार आगाज़ तिलावत-ए-कलाम-ए-पाक से हुआ। विभागाध्यक्ष माहियतुल अमराज़ प्रोफेसर इरफान अहमद ने अतिथियों का विशेष स्वागत करते हुए स्वागत संबोधन पेश किया। एकेडमिक इंचार्ज प्रोफेसर नजीब हंज़ला अम्मरा ने बेहतरीन एवं व्यापक अंदाज़ में कॉलेज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास

को रेखांकित करते हुए आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति को जोर्ण एवं असाध्य रोगों के लिए संजीवनी बताया । डॉ तोमर ने नवप्रवेशित छात्रों को अपने मोटिवेशनल एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान से लाभान्वित किया । कॉलेज के संस्थापक, खानदान-ए-उस्मानी के जीवंत वारिस जनाब यस्मनील उस्मानी ने भावुक लहजे में कहा कि यूनानी तिब के प्रचार-प्रसार के संबंध में हमारे बुजुर्गों के पुराने लक्ष्य बना लें। उन्होंने नए छात्र-छात्राओं को विशेष बधाई भी दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज प्रयागराज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर जी.एस. तोमर ने वर्तमान परिदृश्य में आयुष की भूमिका

हमें गर्व है कि हम ऐसी नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो यूनानी तिब में शोध और रचनात्मक क्षमताओं से सुसज्जित होकर इसे सामाजिक एवं वैश्विक स्तर पर आलोकित करेगी। निदेशक यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश प्रोफेसर जमाल अख्तर ने सफल कार्यक्रम की सराहना करते हुए कॉलेज में नए प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। धन्यवाद ज्ञापन पर पी.जी. कोऑर्डिनेटर डॉ. कमरुल हसन लारी ने किया। संचालन डॉ. रखशंदा बेग ने खुशनुमा अंदाज़ में किया और समापन कॉलेज तराना एवं राष्ट्रगान से हुआ।

मुख्यमंत्री योगी ने जंबूरी स्थल का निरीक्षण कर विश्वस्तरीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को 19वें अनुसूच तैयार करने पर जोर दिया। यह आयोग 23 से 29 नवंबर तक वृंदावन कॉलोनी स्थित ‘डिफेंस व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश

और डिजिटल कनेक्टिविटी तक हर व्यवस्था को सर्वोत्तम मानक के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया। यह आयोग 23 से 29 नवंबर तक वृंदावन कॉलोनी स्थित ‘डिफेंस एक्सपो ग्राउंड’ में होगा। उत्तर प्रदेश



दिये। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विश्वस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे। मुख्यमंत्री ने जंबूरी में शामिल होनेवाली महिला कैडेट्स की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित का विशेष निर्देश दिया। उन्होंने आवास, स्वच्छता, सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं

61 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद इस प्रतिष्ठित डायमंड जुबली संस्करण की मेजबानी कर रहा है। जंबूरी में देशभर के कैडेट भाग लेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, 300 एकड़ में फैले जंबूरी परिसर को 32 हजार प्रतिभागियों और तीन हजार स्टाफ सदस्यों के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे।

दक्षिण अफ्रीका पहुंचे पीएम मोदी, जी-20 लीडर्स समिट में लेंगे हिस्सा

जोहानिसबर्ग। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अफ्रीका में पहली बार आयोजित हो रहे जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को तीन दिवसीय यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी20 शिखर सम्मेलन से इतर छठे आईबीएसए (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वह वसुंधैव कुटुंबकम तथा ‘एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य’ की भावना के अनुरूप भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग रवाना होने से पूर्व पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ‘मैं दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हूं। यह शिखर सम्मेलन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसका आयोजन अफ्रीका में हो रहा है। इसमें अनेक वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।’

कई नेताओं से भी करेंगे मुलाकात
शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री के जोहानिसबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी

समूह का लगاتार चौथा शिखर सम्मेलन होगा, जो ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से पहले जी20 की अध्यक्षताएं क्रमशः



संभावना है। वहां वह छठे आईबीएसए (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। **तीन सत्रों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी**
प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन के तीनों सत्रों को संबोधित करेंगे। यह जी20

ब्राजील (2024), भारत (2023) और इंडोनेशिया (2022) द्वारा की गई थीं। जी20 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल हैं।

मणिपुर में आरएसएस प्रमुख ने जनजातीय नेताओं को संबोधित किया बोले- परिवार के अंदर ही सुलझाने चाहिए मुद्दे

इंफाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को मणिपुर की राजधानी इंफाल में जनजातीय नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सामाजिक एकता का आह्वान किया और कहा कि संघ समाज को सशक्त करने के लिए समर्पित संस्था है। अपने तीन दिवसीय मणिपुर दौरे के दूसरे दिन भागवत ने इंफाल में जनजातीय नेताओं से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा ‘आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं है। इसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को पूर्ण बनाने के लिए गठित हुआ है।’ उन्होंने कहा कि संघ न राजनीति करता है, न किसी संगठन को दूर से नियंत्रित करता है। आरएसएस केवल मित्रता, स्नेह और सामाजिक सौहार्द के माध्यम से कार्य करता है। भारत की सभ्यता आधारित निरंतरता पर जोर देते हुए भागवत ने कहा, ‘हम साझा चेतना के कारण एक हैं। विविधता के बावजूद हम एक ही सभ्यतागत परिवार से हैं। एकता

हमेशा समानता की मांग नहीं करती।’ उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि आंतरिक विघटन को दूर

पर कैसे काम करता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सभ्यता को लेकर प्रतिबद्धता के साथ समाज की भलाई के लिए काम करने वाला हर



करने के उद्देश्य से हुई थी और डॉ. केबी हेडगेवार ने समाज को जोड़ने का प्रयास किया। भागवत ने कहा कि ‘आरएसएस मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण का आंदोलन है।’ उन्होंने सभी को संघ की शाखाओं में जाकर यह समझने की सलाह दी कि संघ जमीनी स्तर

व्यक्ति अधोषिक्त स्वयंसेवक है। जनजातीय नेताओं के सवालों के भी दिए जवाब जनजातीय नेताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर मोहन भागवत ने कहा कि ये राष्ट्रीय चिंताएं हैं। उन्होंने आत्मनिर्भरता और संविधान के भीतर समाधान खोजने पर बल दिया। उन्होंने

कहा, ‘परिवार के मुद्दे परिवार के अंदर ही सुलझाए जाने चाहिए। संवाद एकल पर आधारित होना चाहिए, न कि सौदेबाजी पर।’ उन्होंने यह भी कहा कि कई क्षेत्रीय मुद्दों और विभाजनों की जड़ें औपनिवेशिक नीतियों में रही हैं। भागवत ने जनजातीय नेताओं से अपनी स्वदेशी परंपराओं, भाषाओं और लिपियों पर गर्व करने और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी स्वदेशी जीवनशैली अपनाने का आग्रह किया। युवा नेताओं से अलग बातचीत में, उन्होंने युवाओं से कहा कि भारत कोई नया राष्ट्र नहीं, बल्कि एक प्राचीन और निरंतर सभ्यता है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस शाखाएं जिम्मेदार, सक्षम और निस्वार्थ नागरिकों को तैयार करने का काम करती हैं, जो अपनी प्रतिभा और क्षमता देश के लिए समर्पित करते हैं।

चीन पर मोदी सरकार ने ले लिया इतना बड़ा फैसला, जानकर जिनपिंग भी हैरान!

नई दिल्ली। भारत ने दुनिया भर में भारतीय मिशनों और वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से आवेदन करने वाले चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा खोल दिया है। दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएससी) पर लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद अपने संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। यह कदम भारत द्वारा जुलाई में चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू करने के चार महीने बाद उठाया गया है। अप्रैल-मई 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध शुरू होने के बाद चीनी नागरिकों के वीजा निलंबित कर दिए गए थे। गलवान घाटी में सैन्य टकराव और एक क्रूर झड़प, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और कम से कम चार चीनी सैनिक मारे गए, ने द्विपक्षीय संबंधों को छह दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया। इस मामले से परिचित लोगों ने शुक्रवार

को बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा खोल दिए गए।



इस कदम के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। नाम न छापने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि भारत और

चीन ने हाल के महीनों में संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए कई ‘जन-केंद्रित कदमों’ पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि दोनों

सामान्य बनाने के अन्य कदमों में ग्रीष्मकाल में तिब्बत क्षेत्र के पवित्र स्थलों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का समझौता, विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के लिए वीजा सुविधा और राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव शामिल हैं। इससे पहले, भारत ने जुलाई में चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू कर दिया था, जिससे वे बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास और शंघाई, वांगझू और हांगकांग स्थित वाणिज्य दूतावासों में आवेदन कर सकते थे। दोनों पक्षों के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपरोक्त उद्धृत व्यक्तियों में से एक ने बताया कि इन सभी कदमों का उद्देश्य दोनों देशों के नेताओं के मार्गदर्शन में रेखांकित करती है, क्योंकि अधिकारी बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं और पीढ़ियों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

दुर्घट एयरशो में भारत निर्मित एचएएल तेजस लड़ाकू विमान। यह विमान अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक बड़ी भीड़ के सामने एक प्रदर्शन उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे हवा में घना काला धुआं फैल गया और दर्शकों में दहशत फैल गई। रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय एचएएल तेजस स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 बजे भीड़ के लिए एक प्रदर्शन उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपातकालीन दल ने शहर-राज्य के दूसरे हवाई अड्डे पर, जहाँ यह प्रमुख विमानन कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, घटना पर प्रतिक्रिया दी। दुर्घटना के बाद पायलट की स्थिति तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाई। **तेजस क्या है?**

एचएएल वेबसाइट पर दिए गए विवरण के अनुसार, तेजस 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे आक्रामक हवाई सहायता, निकट युद्ध और ज़मीनी हमलों के अभियानों के लिए डिज़ाइन किया

परिवार में वायु सेना और नौसेना दोनों के लिए एकल-सीट लड़ाकू संस्करण, साथ ही प्रत्येक सेवा के लिए दो-सीट प्रशिक्षक संस्करण शामिल हैं। एचएएल वेबसाइट के अनुसार, यह



गया है। बहुमुखी प्रतिभा के लिए निर्मित, इसे ज़मीनी और समुद्री अभियानों के प्रतिक्रिया दी। दुर्घटना के बाद पायलट की स्थिति तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाई। **तेजस क्या है?**

पाकिस्तान में अब कहां हो गया ब्लास्ट, 15 लोगों की मौत

फैसलाबाद। पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जिले के मलिकपुर में एक रासायनिक कारखाने में बॉयलर फटने से कम से कम 15 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। विस्फोट सुबह-सुबह हुआ, जिससे आस-पास की कई इमारतें ढह गईं, जिनमें एक फ़ैक्टरी की इमारत भी शामिल थी। फैसलाबाद के उपायुक्त राजा जहाँगीर अनवर ने संवाददाताओं को बताया कि बचाव अभियान जारी है और मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका है। अनवर ने कहा कि अब तक बचाव दल ने मलबे से 15 शव निकाले हैं और सात घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उन्होंने आगे

कहा कि बचाव दल मलबा हटाने में लगे हुए हैं। जिले की पूरी मशीनरी बचाव कार्य में लगी हुई है। पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. उस्मान अनवर ने प्रभावी खोज और बचाव अभियान सुनिश्चित करने के लिए रेस्क्यू 1122, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों सहित सभी आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के निर्देश जारी किए। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने फैसलाबाद आयुक्त से घटना

के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र के अन्य रासायनिक कारखानों की सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। अधिकारी भविष्य में इसी तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए औद्योगिक और अन्य प्रोटोकॉल के पालन की भी समीक्षा कर रहे हैं। यह दुखद घटना क्षेत्र में औद्योगिक सुरक्षा मानकों को लेकर चिंताओं को रेखांकित करती है, क्योंकि अधिकारी बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं और पीढ़ियों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

बांग्लादेश में शुक्रवार सुबह 5.5 तीव्रता का भूकंप आने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इसके प्रभाव से पूरे पश्चिम बंगाल में झटके महसूस किए गए। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, भूकंप सुबह 10:08 से 10:10 बजे के बीच कोलकाता, मालदा, नादिया, कूचबिहार और कई अन्य जिलों में कुछ सेकंड के लिए महसूस किया गया। दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर सहित पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, पश्चिम बंगाल के अलावा, पूर्वोत्तर भारत के कई

हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप का केंद्र ढाका के घोराल में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के आचार्य श्रुक्वार तड़के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाहर झकड़ा होते दिखाई दे रहे थे। भूकंप के कारण ढाका में बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच चल रहा टेस्ट मैच भी कुछ देर के लिए बाधित रहा। हालाँकि, कुछ मिनट बाद खेल फिर से शुरू हो गया और किसी नुकसान की खबर नहीं है।